NEXT IAS

भारतीय अर्थव्यवस्था

सिविल सेवा परीक्षा 2027

MADE EASY PUBLICATIONS
द्वारा प्रकाशित

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.
कॉर्पोरेट कार्यालय: 44-A/4, कालू सराय
(हौज़ ख़ास मेट्रो स्टेशन के निकट), नई दिल्ली-110016
संपर्क सूत्र: 011-45124660, 8860378007
ई-मेल करें: infomep@madeeasy.in
विज़िट करें: www.madeeasypublications.org

भारतीय अर्थव्यवस्था

© **कॉपीराइट: Made Easy Publications Pvt. Ltd.**

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, पुनर्मुद्रण, प्रस्तुतीकरण और किसी ऐसे यंत्र में संग्रहण नहीं किया जा सकता, जिससे इसकी पुनर्प्राप्ति की जा सकती हो अथवा इसका स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार) से उपर्युक्त उल्लिखित प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

प्रथम संस्करण: 2024
द्वितीय संस्करण: 2025
तृतीय संस्करण: 2026

विषयसूची

भारतीय अर्थव्यवस्था

इकाई–I: अर्थशास्त्र का परिचय

अध्याय 1

अर्थशास्त्र के मूलभूत तत्त्व
(Fundamentals of Economics)....2

1.1 मूल अवधारणाएँ (Basics)....2
1.2 उत्पादन के कारक (Factors of Production)....2
1.3 वस्तुओं के प्रकार (Types of Goods)....3
1.4 अर्थशास्त्र का अध्ययन (Study of Economics)....4
1.5 अर्थव्यवस्था में विचारधाराएँ (Schools of Economic Thought)....4
1.6 अर्थव्यवस्था के प्रकार (Types of Economy)....5
1.6.1 राज्य की भूमिका के संदर्भ में (In Terms of Role of State)....5
1.6.2 भारत द्वारा अपनाया गया मॉडल (Model Adopted by India)....6
1.6.3 प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में (In Terms of Per Capita Income)....7
1.7 संरचनात्मक संघटक (Structural Composition)....7
1.8 भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Transformation of Indian Economy)....8
1.8.1 विशिष्ट संरचनात्मक परिवर्तन (Peculiar Structural Changes)....8
1.8.2 भारतीय अर्थव्यवस्था के असममित संरचनात्मक रूपांतरण के कारण (Reasons for Asymmetric Structural Transformation of Indian Economy)....9

अध्याय 2

व्यष्टि अर्थशास्त्र (Microeconomics)....11

2.1 मूल अवधारणाएँ (Basic Concepts)....11
2.1.1 चयन का सिद्धांत (Theory of Choice)....11
2.2 माँग (Demand)....11
2.2.1 माँग वक्र (Demand Curve)....11
2.2.2 माँग का नियम (Law of Demand)....12
2.2.3 माँग के नियम की पूर्वधारणाएँ (Assumptions to the Law of Demand)....12
2.2.4 आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव (Income Effect and Substitution Effect) 12
2.2.5 माँग के नियम के अपवाद (Exceptions to the Law of Demand)....12
2.2.6 माँग की लोच (Demand Elasticity)....13
2.2.7 माँग की लोच के प्रकार (Types of Demand Elasticity)....13
2.3 आपूर्ति (Supply)....16
2.3.1 आपूर्ति वक्र (Supply Curve)....16
2.3.2 आपूर्ति का नियम (Law of Supply)....16
2.3.3 आपूर्ति के नियम की मान्यताएँ (Assumptions to the Law of Supply)....16
2.3.4 आपूर्ति की लोच (Supply Elasticity)....17
2.4 बाज़ार संतुलन (Market Equilibrium)....17
2.5 बाज़ार संरचना (Market Structure)....17
2.5.1 पूर्ण प्रतिस्पर्धा (Perfect Competition)....17
2.5.2 एकाधिकार (Monopoly)....18
2.5.3 एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा (Monopolistic Competition)....18
2.5.4 अल्पाधिकारवादी (Oligopoly)....19
2.5.5 एकक्रेताधिकार (Monopsony)....19
2.6 लाभ निर्धारण का अर्थशास्त्र (Economics of Profit Determination)....20

अध्याय 3

राष्ट्रीय आय लेखांकन
(National Income Accounting)....22

3.1 परिचय (Introduction)....22
3.2 राष्ट्रीय आय लेखांकन के उपयोग (Uses of NI Accounting)....22
3.3 आय का चक्रीय प्रवाह (Circular Flow of Income)....22
3.3.1 एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह (Circular Flow of Income in a Simple Economy)....22
3.3.2 बचत एवं निवेश के साथ आय का चक्रीय प्रवाह (Circular Flow of Income with Saving and Investment)....23
3.3.3 हितधारक के रूप में सरकार के साथ आय का चक्रीय प्रवाह (Circular Flow of Income with Government as a Stakeholder)....23

3.3.4 चार क्षेत्रों वाली खुली अर्थव्यवस्था में प्रवाह: बाह्य क्षेत्र को जोड़ना (Flows in the Four Sector Open Economy: Adding Foreign Sector) 23

3.3.5 चक्रीय प्रवाह का महत्त्व (Importance of Circular Flow) 24

3.4 बुनियादी अवधारणाएँ (Basic Concepts) 24

3.4.1 सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 24

3.4.2 सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) 24

3.4.3 विदेश से निवल कारक आय (Net Factor Income from Abroad) 25

3.4.4 सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीतिकारक (GDP Deflator) 25

3.4.5 सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीतिकारक (GNP Deflator) 25

3.4.6 सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर (Difference between GDP and GNP) 25

3.4.7 सकल मूल्यवर्धित/संवर्धन (Gross Value Added) 25

3.5 सकल घरेलू उत्पाद/सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अनुमान लगाने की विधियाँ (Methods of Estimating GDP/GNP) 26

3.5.1 आय दृष्टिकोण (Income Approach) 26

3.5.2 उत्पाद दृष्टिकोण (Output Approach) 26

3.5.3 नई सकल घरेलू उत्पाद शृंखला (New GDP Series) 27

3.5.4 नई जीडीपी शृंखला का आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis of New GDP Series) 27

3.6 राष्ट्रीय आय का आकलन करने में कठिनाइयाँ (Difficulties in Estimating NI) 28

3.7 सकल घरेलू उत्पाद: वास्तविक संकेतक नहीं (GDP: Not a True Indicator) 28

3.8 विकास (Development) 30

3.8.1 संवृद्धि एवं विकास: एक तुलना (Growth and Development: A Comparison) 30

3.8.2 विकास पर अमर्त्य सेन के विचार (Amartya Sen on Development) 31

3.9 विकास के मॉडल (Models of Development) 31

3.9.1 हैरोड-डोमर ग्रोथ मॉडल (Harrod-Domar Growth Model) 31

3.9.2 लुईस संरचनात्मक परिवर्तन (द्वैध-क्षेत्र मॉडल [Lewis Structural Change (Dual-Sector) Model] 32

3.9.3 रोस्तोव का मॉडल (Rostow's Model) 32

3.10 भारत में विकास (Development in India) 32

3.11 हरित सकल घरेलू उत्पाद (Green GDP) 35

इकाई-II: मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति

अध्याय 4

भारत में सामाजिक-आर्थिक नियोजन (Socio-Economic Planning in India) 38

4.1 परिचय (Introduction) 38

4.2 नियोजन की आवश्यकता (Need for Planning) 38

4.3 संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions) 39

4.4 नियोजन के उद्देश्य (Objectives of Planning) 39

4.5 नियोजन के प्रकार (Types of Planning) 40

4.6 पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास (History of FYPs) 41

4.6.1 भारत की स्वतंत्रता से पूर्व की योजनाएँ 41

4.6.2 भारतीय योजनाओं के चार चरण (Four Phases of Indian Plans) 41

4.7 उदारीकरण के युग में नियोजन की प्रासंगिकता (Relevance of Planning in Era of Liberalization) 45

4.8 उपलब्धियाँ और असफलताएँ (Achievements and Failures) 46

4.8.1 उपलब्धियाँ (Achievements) 46

4.8.2 विफलताएँ (Failures) 46

4.9 नीति आयोग (NITI Aayog) 46

4.9.1 परिचय (Introduction) 46

4.9.2 स्थापना के कारण (Reasons for Establishment) 47

4.9.3 नीति आयोग द्वारा उठाए गए कदम (Actions Taken by NITI Aayog) 48

4.9.4 नीति आयोग के निष्पादन का मूल्यांकन (Evaluation of NITI Aayog's Performance) 51

4.9.5 नीति आयोग में सुधार के लिए सुझाव: पुनर्गठित नीति आयोग 2.0 (Suggestions to improve NITI Aayog: REVAMPED NITI AAYOG 2.0) ..53

अध्याय 5

मुद्रा एवं मौद्रिक नीति (Money and Monetary Policy) 55

5.1 मुद्रा (Money) 55

5.2 मुद्रा के प्रकार (Types of Money) 55

5.3 मुद्रा आपूर्ति (Money Supply)....56
5.3.1 नए मौद्रिक समुच्चय (New Monetary Aggregates)....57
5.3.2 मुद्रा की चलन गति (Velocity of Money)....58
5.4 मौद्रिक नीति (Monetary Policy)....58
5.4.1 भारत में मौद्रिक नीति (Monetary Policy in India)....59
5.4.2 मौद्रिक नीति के प्रकार (Types of Monetary Policy)....61
5.5 मौद्रिक नीति संचरण (Monetary Policy Transmission)....66
5.5.1 मौद्रिक नीति संचरण का विकास (Evolution of Monetary Policy Transmission)....67
5.5.2 मौद्रिक नीति प्रसारण की विफलता के कारण (Reasons for Failure of Monetary Policy Transmission)....67
5.5.3 भारत में मौद्रिक नीति की सीमाएँ (Limitations of Monetary Policy in India)....68
5.5.4 मौद्रिक नीति ट्रिलेमा (Monetary Policy Trilemma)....68
5.6 तरलता जाल (Liquidity Trap)....69
5.6.1 मात्रात्मक सहजता (Quantitative Easing - QE)....70
5.6.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्टरलाइजेशन (Sterilization by RBI)....70

अध्याय 6

भारत में बैंकिंग प्रणाली

(Banking System in India)....73
6.1 परिचय (Introduction)....73
6.1.1 उत्पत्ति (Origin)....73
6.1.2 ब्रिटिश शासन के दौरान बैंकों का उद्देश्य (Purpose of Banks During British Rule)....73
6.2 भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India)....73
6.2.1 उद्देश्य (Objectives)....74
6.2.2 स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीयकरण (Nationalization after Independence)..74
6.2.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य (Functions of RBI)....74
6.2.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रकाशन (Publications of RBI)....82
6.2.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के आय एवं व्यय (Income and Expenditure of RBI)....82
6.2.6 केंद्रीय बैंक एवं सरकार के बीच मुद्दे (Issues between the Central Bank and Government)....83
6.2.7 अधिशेष का हस्तांतरण (Transfer of Surplus)....84
6.3 भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Banks in India)....85
6.3.1 राष्ट्रीयकरण (Nationalisation)....85
6.3.2 आवश्यकता (Need)
6.3.3 लाभ (Advantages)....86
6.3.4 समस्याएँ (Problems)....87
6.4 भारत में बैंकों के प्रकार (Types of Banks in India)...87
6.4.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Scheduled Commercial Banks)....88
6.4.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks)....88
6.4.3 अनुसूचित सहकारी बैंक (Scheduled Cooperative Banks)....89
6.4.4 विकास बैंक (Development Banks)....92
6.4.5 औद्योगिक बैंक (Industrial Banks)....94
6.4.6 विभेदित बैंक बनाम सार्वभौमिक बैंक (Differentiated Banks vs Universal Banks)....94
6.4.7 लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks)....94
6.4.8 भुगतान बैंक (Payment Banks)....96
6.4.9 प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंक (Domestic Systemically Important Bank: D-SIB)....97
6.5 बैंकिंग क्षेत्र में सुधार (Reforms in Banking Sector)...97
6.5.1 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग का विकास (Evolution of Public Sector Banking)....97
6.5.2 नरसिम्हन समिति द्वारा अनुशंसित सुधार (Narsimhan Committee Reforms)....98
6.5.3 बेसल समझौता (Basel Accord)....99
6.5.4 पूँजी पर्याप्तता अनुपात को समझना (Understanding Capital Adequecy Ratio)....100
6.5.5 पूँजी पर्याप्तता अनुपात से संबंधित शब्द (Terms Related to Capital Adequacy Ratio)....101
6.6 बैंकिंग क्षेत्र में निहित चुनौतियाँ (Challanges in Banking Sector)....103
6.6.1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी के मामले (Fraud Cases in Public Sector Banks)....103
6.6.2 बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Rising NPAs)....104
6.6.3 दोहरी तुलन-पत्र समस्या (Twin Balance Sheet Problem)....107

6.7 चार 'आर' समाधान प्रक्रिया (Four R Resolution Process) ... 108
6.7.1 तनावग्रस्त संपत्तियों की पहचान (Recognition of Stressed Assets) ... 108
6.7.2 बैंकों का पुनर्पूंजीकरण (Recapitalisation of Banks) ... 110
6.7.3 गैर-निष्पादित परिसंपत्ति का समाधान (Resolution of NPA's) ... 111
6.7.4 सुधार (Reforms) ... 117
6.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (Non-Banking Finance Companies) ... 123
6.9 बैंकिंग क्षेत्र में समकालीन प्रवृत्तियाँ (Contemporary Topics in Banking) ... 126
6.9.1 नियो बैंक (Neo Banks) ... 126
6.9.2 ऑन टैप लाइसेंसिंग (On Tap Licencing) ... 126
6.9.3 निगम क्षेत्र को बैंकों के स्वामित्व का प्रस्ताव (Proposal of Corporates Owning Banks) ... 127
6.9.4 अकाउंट एग्रीगेटर (Account Aggregators- AA) ... 128

अध्याय 7

वित्तीय बाज़ार (Financial Markets) ... 131
7.1 बाज़ार (Market) ... 131
7.2 बाज़ारों के प्रकार (Types of Markets) ... 131
7.3 वित्तीय प्रणालियाँ (Financial Systems) ... 131
7.3.1 वित्तीय बाज़ार (Financial Market) ... 131
7.3.2 मुद्रा बाज़ार (Money Market) ... 133
7.3.3 मुद्रा बाज़ार और पूँजी बाज़ार में समानताएँ (Similarities in Money Market and Capital Market) ... 135
7.4 पूँजी बाज़ार (Capital Market) ... 136
7.4.1 पूँजी बाज़ार की आवश्यकता (Need for Capital Market) ... 136
7.4.2 भारत में पूँजी बाज़ार का विकास (Evolution of Capital Market in India) ... 136
7.4.3 भारत के स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchanges of India) ... 137
7.4.4 पूँजी बाज़ार के घटक (Components of Capital Market) ... 138
7.5 पूँजी बाज़ार के प्रकार (Types of the Capital Market) ... 138
7.5.1 प्राथमिक बाज़ार (Primary Market) ... 138
7.5.2 द्वितीयक बाज़ार/शेयर बाज़ार (Secondary Market/Stock Market) ... 141
7.5.3 तृतीयक और चतुर्थ बाज़ार (Third and Fourth Markets) ... 143
7.6 पूँजी बाज़ार के प्रपत्र (Instruments of Capital Market) ... 143
7.6.1 इक्विटी (Equity) ... 143
7.6.2 ऋण (Debt) ... 144
7.6.3 बॉण्ड (Bond) ... 145
7.6.4 व्युत्पाद/डेरिवेटिव (Derivatives) ... 151
7.6.5 म्यूचुअल फ़ंड (Mutual Funds) ... 153
7.6.6 एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड [Exchange Traded Funds (ETF's)] ... 155
7.6.7 विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (FCCB) [Foreign Currency Convertible Bond (FCCB)] ... 159
7.6.8 पार्टिसिपेटरी नोट्स (P-Notes) [Participatory Notes (P-Notes)] ... 160
7.6.9 मसाला बॉण्ड (Masala Bonds) ... 161
7.7 भारत में पूँजी बाज़ार का विनियमन (Regulation of Capital Market in India) ... 163
7.8 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) [Securities and Exchange Board of India (SEBI)] ... 164
7.8.1 परिचय (Introduction) ... 164
7.8.2 उद्विकास (Evolution) ... 164
7.8.3 संरचना (Structure) ... 164
7.8.4 शक्तियाँ (Powers) ... 164
7.8.5 कार्य (Functions) ... 165
7.8.6 सेबी की उपलब्धियाँ (SEBI's Achievements) ... 165
7.8.7 सेबी से जुड़े मुद्दे (Issues with SEBI) ... 165
7.8.8 पहल (Initiatives) ... 166
7.9 भारत में शेयर बाज़ार घोटाले (Stock Market Scams in India) ... 167
7.9.1 परिचय (Introduction) ... 167
7.9.2 भारतीय शेयर बाज़ार (ISM) में सुधार के लिए किए गए उपाय [Measures Taken to Reform Indian Stock Market (ISM)] ... 167
7.10 शेल कंपनियों पर व्यापार प्रतिबंध (Trading Restrictions on Shell Companies) ... 168
7.10.1 परिचय (Introduction) ... 168

7.10.2 शेल कंपनी के ख़तरे को रोकने के लिए उठाए गए कदम (Steps taken to Curb the Menace of Shell Company) . 169
7.10.3 सुझाव (Suggestions) ... 169
7.11 वैकल्पिक निवेश निधि (AIFs) [Alternate Investment Funds (AIFs)] ... 169
7.12 स्टार्ट-अप फ़ंडिंग (Start-up Funding) ... 170

अध्याय 8

राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) ... 173
8.1 परिचय (Introduction) ... 173
8.2 राजकोषीय नीति के उद्देश्य (Objectives of Fiscal Policy) ... 173
8.3 राजकोषीय नीति के उपकरण (Tools of Fiscal Policy) ... 174
8.4 राजकोषीय नीतियों के प्रकार (Types of Fiscal Policies) ... 174
8.5 भारत में बजट (Budgeting in India) ... 174
8.5.1 बजट निर्माण (Budget Formulation) ... 175
8.5.2 बजट अधिनियमन (Budget Enactment) ... 175
8.6 सरकारी बजट के घटक (Components of Government Budget) ... 176
8.6.1 राजस्व बजट (Revenue Budget) ... 177
8.6.2 पूँजीगत बजट (Capital Budget) ... 177
8.7 घाटा (Deficit) ... 179
8.7.1 प्रकार (Types) ... 179
8.7.2 राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (Financing Fiscal Deficit) ... 180
8.7.3 बाज़ार से उधार लेना (Borrowing from the Market) ... 180
8.7.4 घाटे का मुद्रीकरण (Monetisation of the Deficit) ... 181
8.7.5 राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) 182
8.8 सरकारी बजट के प्रकार (Types of Government Budgeting) ... 184
8.9 बजटीय प्रणाली में कमियाँ (Shortcomings in Budgetary System) ... 187
8.10 बजट से भिन्न वित्तपोषण/ऑफ-बजट फ़ाइनेंसिंग (Off Budget Financing) ... 187
8.11 बजटीय सुधार (Budgetary Reforms) ... 188
8.12 सरकारी ऋण (Government Debt) ... 190
8.12.1 सरकारी ऋण का वर्गीकरण (Classification of Government Debt) .. 190
8.12.2 सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी [(Public Debt Management Agency (PDMA)] ... 191
8.13 अतिरिक्त अवधारणाएँ (Additional Concepts) ... 193
8.13.1 अर्थोपाय अग्रिम [Ways and Means Advances (WMA)]. 193
8.13.2 राजकोषीय खिंचाव (Fiscal Drag) ... 193
8.13.3 राजकोषीय तटस्थता (Fiscal Neutrality) ... 194
8.13.4 क्राउडिंग आउट प्रभाव (Crowding Out Effect) ... 194
8.13.5 पंप प्राइमिंग (Pump Priming) ... 194
8.13.6 आर्थिक प्रोत्साहन (Economic Stimulus) ... 194
8.13.7 कर व्यय (Tax Expenditure) ... 194
8.13.8 15वाँ वित्त आयोग – संदर्भ की शर्तें (15th Finance Commission – Terms of Reference) ... 195
8.13.9 भारत में राजकोषीय परिषद् (Fiscal Council in India) ... 197
8.13.10 वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद् [Financial Stability and Development Council (FSDC)] ... 198
8.14 काला धन (Black Money) ... 198
8.14.1 प्रभाव (Impacts) ... 198
8.14.2 सरकार की पहल (Government's Initiatives) ... 198
8.14.3 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (International Cooperation) ... 199
8.14.4 आगे की राह (Way Forward) ... 199

अध्याय 9

कराधान (Taxation) ... 201
9.1 परिचय (Introduction) ... 201
9.2 करों के प्रकार (Types of Taxes) ... 201
9.2.1 प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) ... 201
9.2.2 अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) ... 206
9.3 मूल अवधारणाएँ (Basic Concepts) ... 212
9.4 कराधान में नवीनतम अवधारणाएँ (Recent Concepts in Taxation) ... 217
9.4.1 रोबोट टैक्स (Robot Tax) ... 217
9.4.2 प्रत्यक्ष कर संहिता (Direct tax code) ... 217
9.4.3 सामान्य कर परिहार विरोधी नियम (General Anti Avoidance Rule: GAAR) ... 218
9.4.4 न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternative Tax: MAT) ... 218
9.4.5 प्रकल्पित कर (Presumptive Tax) ... 219
9.4.6 उत्क्रमी शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure) ... 219

9.4.7 लाफ़र वक्र (Laffer curve) 220
9.4.8 आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS) 220
9.4.9 दोहरा कराधान बचाव समझौता (Double Taxation Avoidance Agreement: DTAA)..222
9.4.10 कर अपवंचन की अन्य तकनीकें (Other Tax Evasion Techniques) 222
9.4.11 वैश्विक न्यूनतम कर (Global Minimum Tax) 223

9.5 भारत और कर प्रशासन (India and Tax Administration) 224
9.5.1 बेहतर कर प्रशासन के लिए सरकार द्वारा की गई पहल (Initiatives Taken by the Government for Better Tax Administration) 224
9.5.2 कराधान में पूर्वव्यापी संशोधन (Retrospective Amendment to Taxation) 225

अध्याय 10

मुद्रास्फीति (Inflation)...228
10.1 परिचय (Introduction) 228
10.1.1 मूल्य और मूल्य स्तर की संकल्पना (Concept of Price and Price Level) 228
10.2 मुद्रास्फीति के प्रकार (Types of Inflation) 228
10.3 मुद्रास्फीति के प्रभाव (Effects of Inflation) 232
10.4 मुद्रास्फीति की माप (Measures of Inflation) 233
10.5 व्यापार चक्र (Business Cycle) 235
10.5.1 व्यापार चक्र के चरण (Phases of Business Cycle) 235
10.5.2 आर्थिक सुधार के स्वरूप के प्रकार (Types of Shape of Economic Recovery) 236

इकाई-III: समावेशी संवृद्धि एवं कृषि

अध्याय 11

ग़रीबी, असमानता और समावेशी विकास (Poverty, Inequality & Inclusive Growth) 240
11.1 परिचय (Introduction) 240
11.1.1 बहुआयामी ग़रीबी (Multidimensional Poverty) 240
11.1.2 बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index) 240
11.2 ग़रीबी के प्रकार (Types of Poverty) 241
11.3 भारत में ग़रीबी का अनुमान (Poverty Estimation in India)............................244
11.3.1 स्वतंत्रता-पूर्व (Pre-Independence) 244
11.3.2 स्वतंत्रता-पश्चात् (Post-Independence) ...244
11.4 भारत में ग़रीबी के कारण (Causes of Poverty in India) 247
11.5 स्वतंत्रता के बाद से भारत में ग़रीबी उन्मूलन (Poverty Alleviation in India Since Independence)..248
11.5.1 पृष्ठभूमि: ग़रीबी और आर्थिक योजना (Background: Poverty and Economic Planning) 248
11.5.2 ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रम (Poverty Alleviation Programmes) 248
11.6 ग़रीबी से निपटने की रणनीति (Strategy for Combating Poverty)....................252
11.6.1 रोज़गार-सघन सतत् तीव्र संवृद्धि (Employment-Intensive Sustainable Rapid Growth).................252
11.6.2 ग़रीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाना (Increasing Effectiveness of Anti-Poverty Programs) 252
11.7 समावेशी संवृद्धि (Inclusive Growth) 253
11.7.1 उद्देश्य (Objective) 253
11.7.2 समावेशी संवृद्धि के तत्त्व (Elements of Inclusive Growth)...........253
11.7.3 भारत में समावेशी संवृद्धि की आवश्यकता (Need for Growth in India)..................254
11.7.4 समावेशी संवृद्धि प्राप्त करने में चुनौतियाँ (Challenges in Achieving Inclusive Growth) 254
11.7.5 सरकार द्वारा उठाए गए कदम (Steps Taken by Government)............255
11.8 वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) 256
11.8.1 अर्थ (Meaning) 256
11.8.2 पूर्व में किए गए प्रयास (Past Efforts)........256
11.8.3 महत्त्व (Importance).............................256
11.8.4 चुनौतियाँ (Challenges) 256
11.8.5 वित्तीय समावेशन पर पहल (Initiatives on Financial Inclusion) 257
11.8.6 आरबीआई द्वारा वर्तमान में वित्तीय समावेशन पहल (Recent Financial Inclusion Initiative by RBI)..................257

11.8.7 वित्तीय समावेशन योजनाएँ और कार्यक्रम (Financial Inclusion Schemes and Programmes)....258

11.9 सूक्ष्मवित्त (Microfinance)....260

11.10 सार्वभौमिक बुनियादी आय (Universal Basic Income-UBI)....262

11.10.1 अर्थ (Meaning)....262

11.10.2 आगे की राह (Way Ahead)....262

11.11 निम्न कौशल विनिर्माण (Low Skill Manufacturing)....263

11.11.1 चुनौतियाँ (Challenges)....263

11.11.2 सरकार द्वारा उठाए गए कदम (Steps Taken by Government)....263

अध्याय 12

रोज़गार, कौशल विकास और श्रम सुधार (Employment, Skill Development and Labour Reforms)....265

12.1 रोज़गार (Employment)....265

12.1.1 भूमिका (Introduction)....265

12.1.2 परिभाषा (Definition)....265

12.1.3 रोज़गार से संबंधित प्रमुख शब्द (Key Terms Related to Employment)..265

12.1.4 बेरोज़गारी के प्रकार (Types of Unemployment)....265

12.1.5 रोज़गार/बेरोज़गारी मापन के दृष्टिकोण (Approaches to Measure Employment Unemployment)....267

12.1.6 श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियाँ (Different Categories of Workers)....267

12.1.7 महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष (Important Observations)....267

12.1.8 आधिकारिक रोज़गार सांख्यिकी रिपोर्ट (Official Employment Statistics Reports)....268

12.1.9 भारत में रोज़गार की प्रवृत्तियाँ (Trends of Employment in India)....268

12.2 रोज़गारविहीन संवृद्धि या अल्परोज़गार (Jobless Growth or Underemployment)....269

12.2.1 भारत में रोज़गारविहीन संवृद्धि के कारण (Reasons for Jobless Growth in India)269

12.2.2 रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ (Strategies to Promote Job Creation)....270

12.3 भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी (Female Labourforce Participation in India)....271

12.3.1 महिला श्रम बल दर संबंधी प्रवृत्ति/रुझान (Trends in Female Labour Force Rate)....271

12.3.2 महिला श्रम शक्ति भागीदारी में बाधाएँ (Constraints in Female Labour Force Participation)....271

12.3.3 महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने के लिए सरकार की पहलें (Initiatives by the Government to increase the Female labour Force Participation Rate)....272

12.3.4 महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने के लिए सुझाव (Suggestion for Increasing Women Labour Force Participation Rate)....273

12.4 कौशल विकास (Skill Development)....274

12.4.1 भूमिका (Introduction)....274

12.4.2 आवश्यकता (Need)....274

12.4.3 चुनौतियाँ (Challenges)....275

12.4.4 सरकार द्वारा उठाए गए कदम (Measures taken by the Government) 275

12.4.5 भारत में कौशल विकास की प्रभावशीलता में सुधार के लिए सुझाव (Suggestion to Improve the Effectiveness of the Skill Development in India)....278

12.5 भारत में प्रशिक्षुता (Apprenticeship in India)....279

12.5.1 भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र (Apprenticeship Ecosystem in India)..279

12.5.2 भारत में प्रशिक्षुता की स्थिति (Status of Apprenticeship in India)....279

12.5.3 प्रशिक्षुता का महत्त्व (Significance of Apprenticeship)....280

12.5.4 मुख्य विशेषताएँ (Salient Features)....280

12.5.5 भारत में खराब प्रशिक्षुता के कारण (Reasons for Poor Apprenticeship in India)....280

12.5.6 भारत में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलें (Government Initiatives to Promote Apprenticeship in India)....280

12.6 भारत में उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development in India)....281

12.6.1 उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली पहलें (Initiatives to Boost Entrepreneurship)281

12.6.2 भारत में उद्यमिता के लिए चुनौतियाँ (Challenges to Entrepreneurship in India) 281
12.6.3 भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलें (Government Initiatives to Promote Entrepreneurship in India) 281
12.6.4 आगे की राह (Way Forward) 282
12.7 कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (Social Security Schemes for Employees) 282
12.8 श्रम सुधार (Labour Reforms) 283
12.8.1 परिचय (Introduction) 283
12.8.2 भारत में श्रम सुधारों की आवश्यकता (Need for Labour Reforms in India) 283
12.9 नई श्रम संहिता (New Labour Codes) 284
12.9.1 मज़दूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) 284
12.9.2 औद्योगिक संबंध संहिता [Industrial Relations (IR) Code] 287
12.9.3 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) 290
12.9.4 व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता विधेयक (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code Bill) 291
12.10 गिग इकॉनमी या गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy) 292
12.10.1 गिग अर्थव्यवस्था के लाभ (Advantages of the Gig Economy) 293
12.10.2 गिग अर्थव्यवस्था की हानियाँ (Disadvantages of the Gig Economy) 293

अध्याय 13

भारत में भूमि सुधार (Land Reforms in India) 296
13.1 परिचय (Introduction) 296
13.2 भूमि सुधारों की पृष्ठभूमि (Background of Land Reforms) 296
13.2.1 भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भू-धारण प्रणाली (Land Tenure Systems during the British Rule in India) 296
13.2.2 औपनिवेशिक काल के दौरान 'भू-स्वामित्व प्रणाली' के परिणाम (Outcomes of Landowning Systems during the Colonial Era) 296
13.3 आज़ादी के बाद से भूमि सुधार (Land Reforms since Independence) 297
13.3.1 ज़मींदारी उन्मूलन (Zamindari Abolition) 297
13.3.2 काश्तकारी सुधार (Tenancy Reforms) 297
13.3.3 हदबंदी कानून (Land Ceiling Laws) 298
13.3.4 भूमि की चकबंदी (Consolidation of Landholdings) 299
13.3.5 सहकारी कृषि (Co-Operative Farming) 299
13.4 भूमि सुधारों के सकारात्मक प्रभाव (Positive Effects of Land Reforms) 300
13.5 भारत में भूमि अभिलेख का कमजोर प्रबंधन (Poor Land Record Management in India) 300
13.6 भूमि अभिलेखों की प्रणाली में सुधार के लिए उठाए गए कदम (Reforms Undertaken to Improve the System of Land Records) 301
13.6.1 निर्णायक स्वामित्व हेतु प्रस्ताव (Proposal of Conclusive Titling) 301
13.6.2 राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (National Land Record Modernization Programme- NLRMP) 301
13.7 भारत में भूमि प्रबंधन (Land Management in India) 302
13.7.1 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) 302
13.7.2 भारत में भूमि विकास बैंक (Land Development Banks in India) 303

अध्याय 14

भारत में कृषि (Agriculture in India) 305
14.1 परिचय (Introduction) 305
14.1.1 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के घटक (Components of Agriculture and Allied Sector) 305
14.1.2 भारतीय कृषि से संबंधित मूलभूत तथ्य (Basic Facts of Indian Agriculture) 305
14.2 भारत में कृषि का महत्त्व/भूमिका (Importance/Role of Agriculture in India) 306
14.3 भारत में कृषि का विकास (Evolution of Agriculture in India) 307
14.3.1 स्वतंत्रता से पूर्व-हरित क्रांति काल तक (Independence to Pre-Green Revolution Period) 307
14.3.2 हरित क्रांति का चरण (Green Revolution Phase) 307
14.3.3 उदारीकरण के बाद (Post-Liberalisation) 308

14.4 भारतीय कृषि की प्रवृत्तियाँ (Trends in Indian Agriculture) 309
14.5 कृषि विकास के निर्धारक – कृषि आगत (Determinants of Agricultural Growth – Agricultural Inputs) 310
14.6 सिंचाई (Irrigation) 310
14.6.1 अर्थ (Meaning) 310
14.6.2 महत्त्व (Importance) 310
14.6.3 सिंचाई के प्रकार/स्रोत (Types/Sources of Irrigation) 311
14.6.4 सूक्ष्म सिंचाई (Micro-Irrigation) 312
14.6.5 सिंचाई से संबंधित सरकारी पहलें (Government Initiatives Related to Irrigation) 313
14.7 बीज (Seeds) 314
14.7.1 परिचय (Introduction) 314
14.7.2 भारत में बीजों के लिए विधायी ढाँचे (Legislative Frameworks for Seeds in India) 314
14.7.3 बीज से संबंधित पहलें (Seed Related Initiatives) 315
14.7.4 भारतीय बीज कार्यक्रम से संबंधित चुनौतियाँ (Challenges in Indian Seed Programme) 315
14.7.5 आनुवंशिक रूप से संशोधित (Genetically Modified- GM) फ़सलें 316
14.8 उर्वरक (Fertilisers) 318
14.8.1 पृष्ठभूमि (Background) 318
14.8.2 स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्त्व (Macro and Micro Nutrients) 318
14.8.3 भारत में प्रयुक्त उर्वरक (Fertiliser Used in India) 319
14.8.4 उर्वरक उत्पादन (Fertiliser Production) 319
14.8.5 उर्वरक सब्सिडी नीति (Fertiliser Subsidy Policy) 319
14.8.6 नीम लेपित यूरिया नीति, 2015 (Neem Coated Urea Policy, 2015) 320
14.8.7 नैनो यूरिया (Nano Urea) 321
14.8.8 उर्वरक से संबंधित अन्य पहलें (Other Initiatives Related to Fertilisers) 322
14.8.9 उर्वरकों से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दे (Important Issues Related to Fertilisers) 324
14.9 कृषि यंत्रीकरण/मशीनीकरण (Farm Mechanisation) 324
14.10 कृषि बीमा (Agricultural Insurance) 325
14.10.1 पिछली योजनाओं से संबंधित मुद्दे (Issues with Earlier Schemes) 325
14.10.2 प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) 326
14.11 कृषि ऋण (Agricultural Credit) 328
14.12 अनुसंधान एवं विस्तार सेवाएँ (Research and Extension Services) 331
14.13 कृषि प्रोद्योगिकी (Agri-Tech) 333
14.14 खाद्य प्रबंधन (Food Management) 335
14.14.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) 335
14.14.2 प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan-PM-AASHA) 337
14.14.3 बाज़ार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme- MIS) 338
14.14.4 मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund) 338
14.14.5 फ़सल कटाई के बाद संचालन (Post Harvest Handling) 338
14.14.6 ख़रीद, भंडारण एवं परिवहन (Procurement, Storage and Transport) 340
14.14.7 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) 344
14.14.8 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) 347
14.14.9 शांता कुमार समिति (Shanta Kumar Committee) 347
14.15 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी (Direct and Indirect Subsidies) 349
14.15.1 कृषि सब्सिडी की आवश्यकता (Need For Farm Subsidies) 349
14.15.2 प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी (Direct Farm Subsidies) 349
14.15.3 अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी (Indirect Farm Subsidies) 349
14.15.4 कृषि सब्सिडी से जुड़े मुद्दे (Issues With Farm Subsidies) 350
14.15.5 संभावित समाधान (Probable Solutions) 350

14.16 कृषि उपज का विपणन
(Marketing of Agricultural Produce) 351
14.16.1 आवश्यकता (Need)...............................351
14.16.2 कृषि विपणन के परिणाम
(Outcomes of Agriculture Marketing) .351
14.16.3 विभिन्न विपणन विधियाँ
(Various Marketing Methods) 351
14.16.4 कृषि उत्पाद विपणन समिति
(Agricultural Produce Market
Committee-APMC).............................351
14.16.5 मॉडल APMC अधिनियम, 2003
(Model APMC Act, 2003)...................352
14.16.6 कृषि उपज और पशुधन विपणन
संवर्धन और सुविधा अधिनियम, 2017
[Agricultural Produce and
Livestock Marketing (Promotion
and Facilitation) Act, 2017] 353
14.16.7 इलेक्ट्रॉनिक-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार
(Electronic-National Agriculture
Market- e-NAM)..................................353
14.16.8 कृषि सुधार और APMC व्यवस्था के
साथ समस्याएँ (Agricultural Reforms
and Problems with APMC Regime) 355
14.16.9 कृषि विपणन में सुधार के लिए प्रमुख
पहलें (Key Initiatives for Reforms in
Agriculture Marketing).......................356
14.17 संविदा कृषि (Contract Farming).........................357
14.18 भूमि पट्टे पर देना (Land Leasing)........................358
14.19 कृषि संकट: किसानों की आत्महत्या
(Agrarian Crisis: Farmers' Suicide)..................360
14.19.1 कारण (Causes)..................................361
14.20 किसानों की आय दुगुनी करना
(Doubling Farmers' Income)............................362
14.21 कृषि ऋण माफ़ी (Farm Loan Waiver)..................364
14.22 जलवायु स्मार्ट कृषि (Climate Smart Agriculture) ...366
14.23 सतत् कृषि (Sustainable Agriculture)..................367
14.24 संरक्षण कृषि (Conservation Agriculture).............368
14.25 जैविक कृषि (Organic Farming)..........................370
14.25.1 जैविक कृषि के सिद्धांत
(Principles of Organic Farming) 370
14.25.2 जैविक खेती में अवसर
(Opportunities for Organic Farming) ..370
14.25.3 जैविक खेती से संबंधित मुद्दे और
चुनौतियाँ (Issues and Challenges of
Organic Farming) 370
14.25.4 भारत में जैविक खेती का परिदृश्य
(Scenario of Organic Farming in
India)..371
14.25.5 जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए
सरकार की पहलें (Government
Initiatives to Promote Organic
Farming)..371
14.25.6 आगे की राह (Way Forward).................372
14.26 शून्य बजट प्राकृतिक खेती
(Zero Budget Natural Farming) 372
14.26.1 शून्य बजट प्राकृतिक खेती का मूल
आधार (Basic Premise of Zero
Budget Natural Farming)...................372
14.26.2 ZBNF के चार स्तंभ
(Four Pillars of ZBNF) 372
14.26.3 जेडबीएनएफ को बढ़ावा देने के लिए
सरकार की पहलें (Government's
Initiatives to Promote ZBNF)...............372
14.27 कृषि आय पर कर आरोपित करना
(Taxing Agricultural Income)...........................373
14.28 किसान उत्पादक संगठन
(Farmer Producer Organisation)......................374
14.28.1 छोटे और सीमांत किसानों को FPO's
के लाभ (Benefit of FPO's to Small
and Marginal Farmers)......................375
14.28.2 FPOs को बढ़ावा देने हेतु पहलें
(Initiatives for the Promotion of FPOs) 375
14.28.3 मज़बूत FPOs के निर्माण में चुनौतियाँ
और संबंधित मुद्दे (Challenges and
Issues in Building Robust FPOs)........375
14.29 कृषि का स्त्रीकरण
(Feminisation of Feminization of Agriculture) ...376

अध्याय 15

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और संबद्ध क्षेत्र
(Food Processing Industry and Allied Sector) 380
15.1 परिचय (Introduction) 380
15.2 इतिहास (History)...381
15.3 महत्त्व (Significance) 381
15.4 सांख्यिकी/आँकड़े (Statistics) 382
15.5 भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएँ
(Potential for Food Processing Industry
in India) 383
15.5.1 भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के
बारे में तथ्य (Facts about Food
Processing Industry in India).............383

15.5.2 भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उज्ज्वल संभावना के कारण (Reasons for Bright Potential of Food Processing in India) 383

15.6 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवस्थिति संबंधी कारक (Locational Factors for Food Processing Industry) 385

15.7 इसमें शामिल चरण और प्रक्रियाएँ (Stages and Processes Involved)....................385

15.8 अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएँ (Upstream and Downstream Requirements) 386

15.9 चुनौतियाँ (Challenges) 388

15.10 सुझाव (Suggestions)..392

15.11 सरकारी योजनाएँ (Government Schemes).............393

15.12 नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authorities)..........398

15.12.1 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) 398

15.12.2 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)....................398

15.12.3 भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) 398

15.13 खाद्य मानक (Food Standards).............................399

15.13.1 भारतीय मानक ब्यूरो (BIS).......................399

15.13.2 कोडेक्स (Codex)..................................400

15.13.3 एगमार्क (AGMARK) 400

15.13.4 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006)..400

15.14 कृषि निर्यात (Agricultural Exports).......................400

15.14.1 कृषि-निर्यात की वर्तमान स्थिति (Present Status of Agri-Exports) 400

15.14.2 कृषि निर्यात नीति, 2018 (Agricultural Exports Policy, 2018) 401

15.14.3 निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाएँ [Recommendations of the High-Level Expert Group (HLEG) to Boost Exports]...................................402

15.14.4 भारत में कृषि निर्यात क्षेत्र (Agri Export Zone in India) 402

15.15 कृषि क्रांतियाँ (Agricultural Revolutions)...............403

15.15.1 पशुपालन (Animal Husbandry) 403

15.15.2 कुक्कुटपालन क्षेत्र (Poultry Sector)...........405

15.15.3 रजत/सिल्वर क्रांति (Silver Revolution)......406

15.15.4 गुलाबी क्रांति (Pink Revolution) 407

15.15.5 श्वेत क्रांति (White Revolution)...............407

15.15.6 नीली क्रांति (Blue Revolution)................408

15.15.7 नीली क्रांति 2.0/नील क्रांति मिशन (Blue Revolution 2.0/Neel Kranti Mission)...411

15.15.8 मधुमक्खीपालन/मीठी क्रांति (Beekeeping/Sweet Revolution) 413

15.15.9 रेशम कीटपालन (Sericulture) 415

15.15.10 कृषि विविधीकरण/इंद्रधनुष क्रांति (Agricultural Diversification/ Rainbow Revolution)...........................417

15.15.11 पौष्टिक अनाज/मोटे अनाज (Nutri-Cereals/Millets).........................419

15.15.12 दलहन (Pulses)....................................421

15.15.13 पीली क्रांति (Yellow Revolution).............422

15.15.14 स्वर्ण क्रांति (Golden Revolution)............424

15.16 द्वितीयक कृषि (Secondary Agriculture)................427

15.16.1 द्वितीयक कृषि के पीछे का दर्शन (Philosophy behind Secondary Agriculture)...427

15.16.2 द्वितीयक कृषि के लाभ (Benefits of Secondary Agriculture) ...427

15.16.3 द्वितीयक कृषि के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता (Special Support Needed for Secondary Agriculture)....428

15.17 सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution)................428

15.17.1 सदाबहार क्रांति की विशेषताएँ (Features of Evergreen Revolution)....428

15.17.2 सदाबहार क्रांति की आवश्यकता (Need for Evergreen Revolution)........428

15.17.3 भारत में सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution in India) 429

15.17.4 नीति आयोग का 'सदाबहार क्रांति' के लिए 3-वर्षीय रोडमैप (NITI Aayog's 3-year Road Map for 'Evergreen Revolution')..429

इकाई-IV: उद्योग एवं आधारभूत संरचना

अध्याय 16

उद्योग (Industry)..432

16.1 परिचय (Introduction) 432

16.2 उद्योगों का विकास (Evolution of Industries) 432

16.2.1 स्वतंत्रता के समय (At the Time of Independence)...........432

16.3 औद्योगिक नीति (Industrial Policy) 433
16.3.1 औद्योगिक नीति के उद्देश्य (Objectives of Industrial Policy)..........433
16.3.2 औद्योगिक नीति संकल्प, 1948 (Industrial Policy Resolution of ,1948) 433
16.3.3 औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 (Industrial Policy Resolution of 1956).434
16.3.4 वर्ष 1965 और 1980 के बीच उद्योग का विकास (Evolution of Industry between 1965 and 1980)....................435
16.3.5 वर्ष 1980, 1985 और 1986 की औद्योगिक नीतियों के संकल्प (Industrial Policy Resolution of 1980, 1985 and 1986) 435
16.3.6 पहली पीढ़ी के सुधार: नई औद्योगिक नीति (First Generation Reform: New Industrial Policy).......................436
16.3.7 नई औद्योगिक नीति, 1991 के तहत पहलें (Initiative under the New Industrial Policy, 1991)......................................436
16.3.8 दूसरी पीढ़ी के सुधार (Second Generation Reforms)............440
16.4 औद्योगिक विकास (Industrial Development)..........441
16.4.1 परिचय (Introduction)............................441
16.4.2 भारत के औद्योगिक केंद्र बनने के कारण (Reasons for India becoming an Industrial Hub)...................................441
16.4.3 विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल (Government Initiatives to Boost Manufacturing).........................442
16.4.4 "मेक इन इंडिया" अभियान का विश्लेषण (Analysis of the "MAKE IN INDIA" Campaign) 442
16.4.5 मेक इन इंडिया अभियान की विफलता के कारण (Reasons For Failure of Make in India Campaign)...................442
16.4.6 नई विनिर्माण नीति (New Manufacturing Policy).........................443
16.5 औद्योगिक पहलें (Industrial Initiatives) 444
16.5.1 औद्योगिक गलियारे (Industrial Corridors).444
16.5.2 राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (National Investment-amp-Manufacturing Zones) 446
16.5.3 आत्मनिर्भर भारत (Atma Nirbhar Bharat) .446
16.5.4 उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme-PLI).....................................447
16.6 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro Small and Medium Enterprises- MSME) 449
16.6.1 परिचय (Introduction)............................449
16.6.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा (New Definition of MSMEs) 449
16.6.3 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का महत्त्व (Importance of MSME Sector)
16.6.4 चुनौतियाँ (Challenges) 451
16.6.5 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलें (Government Initiatives for Promoting MSMEs) 452
16.7 भारत में विभिन्न विनिर्माण उद्योग (Various Manufacturing Industries in India)......455
16.7.1 रक्षा विनिर्माण (Defence Manufacturing) 455
16.7.2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (Electronics Manufacturing) 457
16.8 सेवा क्षेत्र (Service Sector)..................................459
16.8.1 सेवा क्षेत्र का परिचय (Introduction to Service Sector)..........459
16.8.2 पर्यटन क्षेत्र (Tourism Sector)..................460
16.8.3 सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन उद्योग (Information Technology and Business Process Management (IT&BPM) Industry) 461
16.8.4 भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र (Real Estate Sector in India)
16.8.5 दूरसंचार क्षेत्र (Telecom Sector) 466
16.8.6 बीमा क्षेत्र (Insurance Sector) 468
16.8.7 अंतरिक्ष क्षेत्र (Space Sector) 470
16.8.8 भारत में नवाचार (Innovation in India).....474
16.8.9 ई-कॉमर्स (e-Commerce).......................476
16.8.10 भारत में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम (Start up Ecosystem in India) 478
16.9 औद्योगिक प्रदर्शन को मापने के लिए उपकरण (Tools to Measure Industrial Performance).......482
16.9.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production - IIP)...482
16.9.2 आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (Index of Eight Core Industries)..........482
16.9.3 उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries- ASI)......483
16.9.4 क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Managers Index- PMI)....483

अध्याय 17

आधारभूत संरचना तथा निवेश मॉडल (Infrastructure and Investment Models) 484
17.1 परिचय (Introduction) 484
17.2 परिभाषा (Definition) 484

17.3 बुनियादी संरचना के विकास का महत्त्व (Importance of Infrastructure Development) 485
- 17.3.1 बुनियादी ढाँचे के विकास में चुनौतियाँ (Challenges in Infrastructure Development)....................................485

17.4 निवेश मॉडल (Investment Models) 485
- 17.4.1 निवेश को विस्तार से समझना (Understanding Investment in Detail).486
- 17.4.2 निवेश और सकल घरेलू उत्पाद के बीच संबंध (Relation between Investment and GDP).........................486
- 17.4.3 सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership - PPP)......487
- 17.4.4 हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (Hybrid Annuity Model) 491

17.5 बुनियादी संरचना का वित्तपोषण (Infrastructure Financing).................................492
- 17.5.1 आधारभूत संरचना के वित्तपोषण से संबंधित मुद्दे (Issues in Infrastructure Financing) 493
- 17.5.2 सरकार द्वारा किए गए उपाय (Measures taken by Government)......494
- 17.5.3 राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष [National Infrastructure Investment Fund (NIIF)].....................495
- 17.5.4 राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline)........495
- 17.5.5 राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline).........496

17.6 क्षेत्रवार विश्लेषण (Sector-wise Analysis) 499
- 17.6.1 ऊर्जा (Energy)....................................499
- 17.6.2 सौर ऊर्जा (Solar Energy)......................500
- 17.6.3 सौर विनिर्माण रणनीति (Solar Manufacturing Strategy)...........503
- 17.6.4 पवन ऊर्जा (Wind Energy) 503
- 17.6.5 राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति (National Wind-Solar Hybrid Policy) ...505
- 17.6.6 जलविद्युत (Hydroelectricity) 506
- 17.6.7 अपशिष्ट-से-ऊर्जा (Waste-to-Energy)......507
- 17.6.8 जैवभार ऊर्जा (Biomass Energy).............508
- 17.6.9 हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था (Hydrogen Economy) 510
- 17.6.10 विद्युत (Power)....................................512
- 17.6.11 कोयला क्षेत्रक (Coal Sector)...................517
- 17.6.12 सड़क क्षेत्रक (Road Sector) 519
- 17.6.13 विद्युत गतिशीलता (Electric Mobility) 524
- 17.6.14 रेलवे (Railways)..................................526
- 17.6.15 भारतीय रेलवे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल (PPP Model in Indian Railways)................................528
- 17.6.16 बंदरगाह, जहाज़रानी तथा अंतर्देशीय जलमार्ग (Ports, Shipping and Inland Waterways)..............................530
- 17.6.17 भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र (Civil Aviation Sector in India) 531
- 17.6.18 लॉजिस्टिक्स क्षेत्र (Logistics Sector).........533
- 17.6.19 डिजिटल अवसंरचना (Digital Infrastructure) 535
- 17.6.20 डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure)..............537

अध्याय 18

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector Undertakings) 541

18.1 परिचय (Introduction) 541

18.2 सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों की आवश्यकता (Need for Public Sector Undertakings) 541

18.3 सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों के उद्देश्य (Objectives of PSUs).......................................541

18.4 सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों का विकास (Evolution of Public Sector Undertakings)........542

18.5 सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों की चुनौतियाँ (Challenges of PSUs) 543

18.6 सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों का वर्गीकरण (Classification of PSUs)...................................543

18.7 विनिवेश (Disinvestment) 545
- 18.7.1 परिचय (Introduction)...........................545
- 18.7.2 विनिवेश से अपेक्षित उद्देश्य (Objectives Sought from Disinvestment)..................................545
- 18.7.3 विनिवेश के प्रकार (Types of Disinvestment)....................545
- 18.7.4 विनिवेश के लाभ (Benefits of Disinvestment).................546
- 18.7.5 विनिवेश से होने वाली हानियाँ (Disadvantages of Disinvestment)......546
- 18.7.6 विनिवेश की प्रक्रिया (Process of Disinvestment).................547

18.7.7 राष्ट्रीय निवेश कोष (National Investment Fund) 547

18.7.8 सरकार द्वारा अपने विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने के कारण (Reasons for the Government not Meeting its Disinvestment Target)....................548

इकाई–V: बाह्य क्षेत्रक

अध्याय 19

भुगतान संतुलन (Balance of Payments: BOP)..550

19.1 परिचय (Introduction) 550

19.2 भुगतान संतुलन के घटक (Components of BOP).....550

19.2.1 चालू खाता (Current Account) 550

19.2.2 पूँजी खाता (Capital Account) 550

19.2.3 त्रुटियाँ और भूल-चूक (Errors and Omissions).......................551

19.2.4 विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन (Changes in Foreign Exchange Reserves) 551

19.3 भुगतान संतुलन (BOP) और विदेशी मुद्रा भंडार (FOREX) 552

19.3.1 भुगतान संतुलन (BOP) में असंतुलन (Disequilibrium of BOP).....................552

19.3.2 असंतुलन के प्रकार (Types of Disequilibrium) 552

19.3.3 भुगतान संतुलन में असंतुलन/असाम्यता को दूर करने के उपाय (Measures to Overcome Disequilibrium/ Imbalances in BOP) 553

19.4 भुगतान संतुलन संकट (BOP Crisis) 554

19.4.1 भुगतान संतुलन संकट में वैश्विक संस्थानों की भूमिका (Role of Global Institutions in BOP Crisis)...................554

19.5 मुद्रा की परिवर्तनीयता (Convertibility of Currency)..555

19.6 भारत और भुगतान संतुलन (India and BOP) 557

अध्याय 20

विदेशी निवेश (Foreign Investment)...............................561

20.1 विनिमय दर (Exchange Rate)..............................561

20.1.1 विनिमय दर प्रणाली के प्रकार (Types of Exchange Rate System) 561

20.1.2 अवमूल्यन (Devaluation) और पुनर्मूल्यन (Revaluation).........................563

20.1.3 भारत के मुद्रा प्रहस्तन-कर्ता (हेर-फेर करने वाले) देश होने के संबंध में विवाद (Controversy Regarding India Being a Currency Manipulator) 563

20.1.4 विनिमय दर बाज़ारों के प्रकार (Types of Exchange Rate Markets) 564

20.1.5 विनिमय दरों को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Exchange Rates)..564

20.1.6 भारत में विनिमय दर प्रणाली (Exchange Rate System in India) 565

20.1.7 भारत में विनिमय दर प्रबंधन के उद्देश्य (Objectives of Exchange Rate Management in India) 565

20.1.8 सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर [Nominal Effective Exchange Rate (NEER)] 566

20.1.9 वास्तविक प्रभावी विनिमय दर [Real Effective Exchange Rate (REER)] 566

20.2 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserve of India)..................................566

20.3 क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity)................................567

20.3.1 परिचय (Introduction)...........................567

20.3.2 सकल घरेलू उत्पाद (सांकेतिक) और सकल घरेलू उत्पाद (क्रय शक्ति समता) [GDP (Nominal) and GDP (PPP)] 568

20.4 विदेशी निवेश: FDI और FII/FPI (Foreign Investments: FDI and FII/FPI).............569

20.4.1 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment: FDI) 569

20.4.2 विदेशी पोटफ़ोलियो निवेश [Foreign Portfolio Investment (FPI)] 570

20.4.3 विदेशी संस्थागत निवेशक [Foreign Institutional Investor (FII)].....570

20.4.4 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश [Foreign Direct Investment (FDI) in India] 571

20.4.5 FDI के लिए निषिद्ध क्षेत्र (Prohibited Sectors for FDI)................575

20.4.6 कारक जिन पर FDI निर्भर करता है (Factors on which FDI Depends)........575

20.4.7 FDI का महत्त्व (Importance of FDI).......576

20.4.8 FDI की आलोचना (Criticism of FDI) 576

20.4.9 FDI नीति को और अधिक उदार बनाने के लिए सरकार की हालिया पहलें (Recent Government Initiatives to Further Liberalise FDI Policy) 577

20.5 बाह्य वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowings, ECB)..........579

अध्याय 21

विदेश व्यापार (Foreign Trade)........583

21.1 परिचय (Introduction)........583

21.2 विश्व व्यापार में भारत का स्थान (India's Place In World Trade)........583

21.3 भारत में विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy In India)........584

21.3.1 आयात प्रतिबंध और आयात प्रतिस्थापन (Import Restrictions and Import Substitution)........584

21.3.2 निर्यात संवर्धन एवं आयात उदारीकरण (Export Promotion And Import Liberalization)........585

21.3.3 बाह्य उन्मुखीकरण (Outward Orientation)........586

21.4 भारतीय विदेश व्यापार की संरचना (Indian Foreign Trade Structure)........591

21.4.1 आयातित सामग्री (Imported Material)........591

21.4.2 निर्यात बास्केट (Export Basket)........591

21.4.3 व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार संतुलन (Trade Balance With Trading Partners)........592

21.5 भारतीय विदेश व्यापार: एजेंसियाँ (Indian Foreign Trade: Agencies)........592

21.6 विदेश व्यापार नीति, 2015-20 (Foreign Trade Policy, 2015-20)........594

21.7 विदेश व्यापार नीति 2023 (Foreign Trade Policy 2023)........595

21.8 निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ (Export Promotion Schemes)........596

21.9 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (International Cooperation)........598

21.9.1 आर्थिक एकीकरण (Economic Integration)........598

21.9.2 आर्थिक एकीकरण के स्तर (Levels of Economic Integration)........598

21.9.3 विकास का निर्यातोन्मुख मॉडल (Export & Led Model of Development)........600

21.9.4 वैश्विक मूल्य शृंखला (Global Value Chains: GVCs)........602

21.9.5 भारत के मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements of India)........604

21.9.6 आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि (Model Bilateral Investment Treaty)........605

21.9.7 आदर्श बीआईटी के प्रमुख प्रावधान (Important Provisions of Model BIT)........606

21.9.8 भारत-यूके व्यापक-आधारित व्यापार और निवेश समझौता (India-UK Broad-Based Trade and Investment Agreement)........606

21.10 क्षेत्रीय समझौते (Regional Agreements)........607

21.10.1 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) [Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)]........607

21.10.2 ट्रांस-पैसिफ़िक भागीदारी (टीपीपी) [Trans-Pacific Partnership (TPP)]........609

21.10.3 ट्रांस-अटलांटिक व्यापार और निवेश भागीदारी (टीटीआईपी) [Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)]........611

इकाई-VI: अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन

अध्याय 22

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन (International Economic Organizations)........613

22.1 ब्रेटन वुड्स संस्थान (Bretton Woods Institutions)........613

22.2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF)........613

22.2.1 IMF के उद्देश्य (Objectives of IMF)........613

22.2.2 कार्य (Functions)........613

22.2.3 शासन संरचना (Governance Structure)........614

22.2.4 IMF कोटा प्रणाली (IMF Quota System)........614

22.2.5 IMF प्रकाशन (IMF Publications)........615

22.2.6 भारत और IMF (India and IMF)........616

22.2.7 IMF में सुधार की आवश्यकता (Need for Reforms in IMF)........616

22.2.8 सुधारों की माँग (Reforms Demanded)........617

22.2.9 वर्ष 2016 में IMF द्वारा किए गए सुधार (Reforms Taken by IMF in 2016)........617

22.3 विश्व बैंक समूह (World Bank Group)........617

22.3.1 संगठन की संरचना (Organisation Structure)........618

22.3.2 विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट (Important Reports Published by The World Bank)........619

22.3.3 भारत और विश्व बैंक (India and World Bank)........619

22.3.4 विश्व बैंक में सुधार की आवश्यकता (Need for Reforms in World Bank)........620

22.3.5 सुधारों की माँग (Reforms Demanded)........620

22.4 IMF और विश्व बैंक: एक महत्त्वपूर्ण विश्लेषण (IMF and World Bank: A Critical Analysis)........621
22.5 अन्य संस्थाएँ (Other Institutions)..........................622
22.5.1 न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank)...........................622
22.5.2 एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank- ADB) 625
22.5.3 एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (Asian Investment Infrastructure Bank- AIIB)..627
22.5.4 ब्लू डॉट नेटवर्क (Blue Dot Network- BDN) 630
22.5.5 जी-20 (G-20).....................................630
22.5.6 जी-7 (G-7)..635
22.5.7 डी-10 (D-10) 637
22.5.8 आपूर्तिश्रृंखला लचीलापन पहल (Supply Chain Resilience Initiative- SCRI)..................................637

अध्याय 23

विश्व व्यापार संगठन

(World Trade Organization)...640
23.1 परिचय (Introduction) 640
23.2 विश्व व्यापार संगठन के लिए तर्क (Rationale for WTO)...640
23.3 विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य (Objectives of WTO)..640
23.4 विश्व व्यापार संगठन का विकास (Evolution of Wto)..640
23.5 संगठनात्मक संरचना (Organizational Structure) 642
23.6 विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत (Principles of WTO) 643
23.7 डब्ल्यूटीओ समझौते (WTO Agreements) 644
23.7.1 कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture- AoA).......644
23.7.2 व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (Trade Related Intellectual Property Rights) 645
23.7.3 स्वच्छता और पादप-स्वच्छता उपाय [Sanitary and Phyto-Sanitary Measures (SPS)] 648
23.7.4 सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (General Agreement on Trade in Services- GATS)................................648
23.7.5 व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता-ट्रिम्स (Agreement on Trade Related Investment Measures-TRIMS) 649
23.7.6 सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर समझौता (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures- SCM)..649
23.8 महत्त्वपूर्ण मंत्रिस्तरीय बैठकें (Important Ministerial Meets)............................650
23.8.1 दोहा मंत्रिस्तरीय बैठक और दोहा विकास एजेंडा-2001 [Doha Ministerial Meet and Doha Development Agenda (DDA)-2001]......................................650
23.8.2 बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन और बाली पैकेज (Bali Ministerial Conference and Bali Package)..............................651
23.8.3 नैरोबी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Nairobi Ministerial Conference).........651
23.8.4 ब्यूनस आयर्स मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Buenos Aires Ministerial Conference) 652
23.8.5 एमसी12 जेनेवा (MC12 Geneva) 652
23.9 डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र (WTO Dispute Settlement Mechanism).............652
23.9.1 डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र की विफलता (Breakdown in WTO Dispute Settlement Mechanism).........652
23.9.2 विवाद निपटान की प्रक्रिया (Process of Dispute Settlement).........652
23.10 भारत और विश्व व्यापार संगठन (India and WTO) 653
23.10.1 भारत का खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और विश्व व्यापार संगठन (India's Food Security Program and WTO)...............653
23.10.2 एच-1 बी वीज़ा मुद्दा और जीएटीएस (H-1B Visa Issue and GATS) 654
23.10.3 भारत सौर पैनल विवाद एवं ट्रिम्स (India Solar Panel Dispute and TRIMS) 654
23.10.4 भारत-अमेरिका कुक्कुट विवाद (India-US Poultry Dispute)..................655
23.11 भारत और ट्रिप्स बौद्धिक सपंदा अधिकार (India and TRIPS Intellectual Property Rights) .655
23.11.1 भारत और ट्रिप्स से जुड़े मुद्दे (Issues with India's and TRIPS)..........655
23.12 डब्ल्यूटीओ से जुड़े मुद्दे (Issues with WTO) 658
विश्व व्यापार संगठन के सुधार (Reforms of WTO)....659

इकाई I

अर्थशास्त्र का परिचय

1. अर्थशास्त्र के मूलभूत तत्त्व (Fundamentals of Economics) 2

2. व्यष्टि अर्थशास्त्र (Microeconomics) 11

3. राष्ट्रीय आय लेखांकन (National Income Accounting) 22

अध्याय 1

अर्थशास्त्र के मूलभूत तत्त्व (Fundamentals of Economics)

1.1 मूल अवधारणाएँ (Basics)

अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग का विश्लेषण करता है। दूसरे शब्दों में, यह एक प्रकार का निर्धारक है, जो इस तथ्य से संबंधित है कि लोग ख़रीदारी करते समय क्यों और कैसे, जैसी स्थितियों में कौन-सा विकल्प चुनते हैं?

बुनियादी स्तर पर अभाव मुख्य आर्थिक समस्या है, क्योंकि मनुष्य के रूप में हमारे पास असीमित इच्छाएँ (आवश्यकताएँ) होती हैं। इन इच्छाओं को पृथ्वी के संसाधनों की सीमित मात्रा से पूरा नहीं किया जा सकता है। किसी गैर-शून्य क़ीमत (Non-zero Price) वाली वस्तु या सेवा को दुर्लभ या दुष्प्राप्य माना जाता है। उस वस्तु या सेवा का उपभोग करने के लिए आपको कुछ (श्रम या धन) व्यय करना होता है। अभाव न होने पर, लोग उन सभी वस्तुओं का उपयोग कर सकेंगे, जो वे संभवत: उपभोग कर सकते हैं और उन्हें वस्तुओं तथा सेवाओं के बीच चयन या समझौता नहीं करना पड़ेगा। अत: यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र इस तथ्य का अध्ययन है कि समाज किस प्रकार मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करने और उन्हें विभिन्न लोगों के बीच वितरित करने के लिए अपर्याप्त संसाधनों को आवंटित करता है।

1.2 उत्पादन के कारक (Factors of Production)

उत्पादन के कारक उन साधनों को संदर्भित करते हैं, जो आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। उत्पादन के कारकों में भूमि, श्रम, पूँजी और उद्यमिता शामिल हैं।

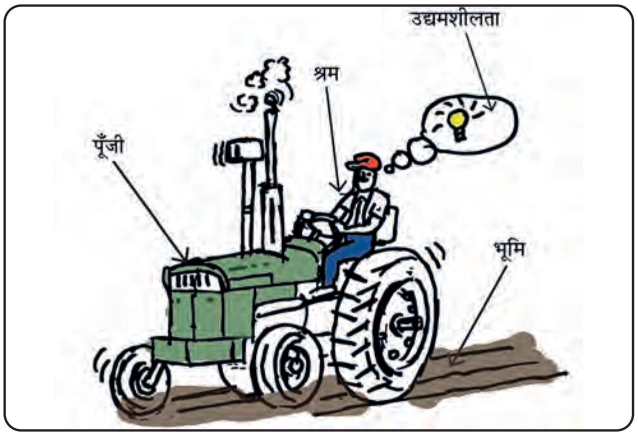

A. भूमि (Land)

- भूमि एक आर्थिक संसाधन है, जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था को क्रियाशील करने वाले प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं।
- इन संसाधनों में लकड़ी, भूमि, मत्स्यन, कृषि योग्य भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं।
- सामान्यत: कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए भूमि एक सीमित संसाधन है। उदाहरण के लिए भारत में वैश्विक जनसंख्या का 17.7% हिस्सा निवास करता है, लेकिन यहाँ वैश्विक भूमि का केवल 2.4% भाग ही उपलब्ध है।

B. श्रम (Labour)

- श्रम, कच्चे माल या राष्ट्रीय संसाधनों को 'उपभोग योग्य वस्तुओं' (Consumable goods) में रूपांतरित करने के लिए उपलब्ध मानव पूँजी का प्रतिनिधित्व करता है।
- मानव पूँजी में वे व्यक्ति शामिल होते हैं, जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान करने और अन्य व्यक्तियों या व्यवसायों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के इच्छुक हैं।
- उत्पादन का यह कारक एक लचीला संसाधन (Flexible resource) है, क्योंकि श्रमिकों को उपभोक्ता वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- श्रमिकों के प्रशिक्षण, शिक्षण और कौशल संवर्धन के माध्यम से मानव पूँजी में भी सुधार किया जा सकता है।

C. पूँजी (Capital)

- पूँजी व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा किए गए टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों (Durable physical assets) में निवेश से संबंधित होती है, जिसका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इन परिसंपत्तियों में भवन, उत्पादन सुविधाएँ, उपकरण और वाहन इत्यादि शामिल होते हैं।
- पूँजी उन मौद्रिक संसाधनों को कहते हैं, जिनका उपयोग कंपनियाँ प्राकृतिक संसाधनों, भूमि और अन्य पूँजीगत वस्तुओं को ख़रीदने के लिए करती हैं।
- इस प्रकार पूँजी अन्य उत्पादों की आपूर्ति में प्रयोग किए जाने वाले मानव निर्मित साधनों को संदर्भित करती है।

D. उद्यमशीलता (Entrepreneurship)

- आर्थिक संसाधन अर्थव्यवस्था में उपलब्ध होते हैं और वे स्वत: उपभोक्ता वस्तुओं में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं।
- उद्यमी, उद्यमशीलता के माध्यम से सामान्य वस्तुओं या सेवाओं को मूल्यवान वस्तुओं एवं सेवाओं में रूपांतरित करते हैं, जिसमें वे आर्थिक संसाधनों को उपभोक्ता उत्पादों में परिवर्तित करने का जोख़िम उठाकर लाभ अर्जित करते हैं।

उत्पादन के कारक

भूमि

प्राकृतिक संसाधन

भूमि एक प्रकृति प्रदत्त उपहार या संसाधन है, जो मानवीय प्रयासों द्वारा निर्मित नहीं है।

पूंजी

मानव निर्मित संसाधन

पूँजी के अंतर्गत औज़ार, उपकरण और उत्पादन में प्रयुक्त कारखाने शामिल हैं।

श्रम

मानव पूँजी

श्रमिकों के अंतर्गत कुशल एवं योग्य व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

उद्यमशीलता

संगठन

उद्यमी उन व्यक्तियों को कहते है, जो नया व्यापार शुरू करते हैं और बाज़ार में उत्पादों को पेश करते हैं।

1.3 वस्तुओं के प्रकार (Types of Goods)

A. अंतिम वस्तुएँ (Final Goods)

उपभोक्ता (व्यक्तिगत या उद्यम) द्वारा ख़रीदी गई कोई भी वस्तु या सेवा अंतिम उपभोग के लिए या आगे के उत्पादन में उपयोग के लिए हो सकती है। इनमें अंतिम वस्तुएँ उत्पादन या रूपांतरण के सबसे अंतिम चरण में होती हैं। इसके पश्चात् वे किसी भी परिवर्तन के चरण से नहीं गुज़रती हैं।

विशेषताएँ:

- वस्तुएँ इस चरण के बाद किसी अन्य निर्माता द्वारा रूपांतरित नहीं की जाती हैं।
- एक बार जब इन्हें बेच दिया जाता है, तो ये बाज़ार की सक्रिय आर्थिक प्रवाह (Active economic flow) प्रक्रिया से बाहर निकल जाती हैं।
- इसके अलावा, ये अपने उपभोग के दौरान अंतिम ख़रीदार द्वारा किए गए परिवर्तनों (रूपांतरण) से गुज़रती हैं।

उदाहरण- उपभोक्ता द्वारा ख़रीदी गई चाय की पत्ती का उसी रूप में उपभोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग पीने योग्य चाय (Drinkable tea) बनाने के लिए किया जाता है, जिसका सेवन किया जाता है। इसी प्रकार, हमारी रसोई में प्रवेश करने वाली अधिकांश वस्तुएँ खाना पकाने की प्रक्रिया के माध्यम से बदल जाती हैं। घर में खाना पकाना एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, भले ही इसमें शामिल उत्पाद परिवर्तन से गुज़रता हो। घर का बना खाना बाज़ार में नहीं बेचा जाता है और इसलिए इसे अंतिम वस्तु नहीं माना जाता है।

B. मध्यवर्ती वस्तुएँ (Intermediate Goods)

अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल उत्पादन में से, बड़ी संख्या में उत्पाद अंतिम खपत के बाद भी न तो समाप्त होते हैं और न ही पूँजीगत वस्तुओं में परिवर्तित होते हैं। इस तरह की वस्तुओं का उपयोग अन्य उत्पादकों द्वारा सामग्री आगत (Input) के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण- ऑटोमोबाइल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली स्टील की चादर (Steel sheets) और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला ताँबा मध्यवर्ती वस्तुएँ हैं। सामान्यत: मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल या आगत के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक रेस्टोरेंट में खाना पकाने या चाय बनाने का कार्य किया जाता है और इसमें पका हुआ उत्पाद ग्राहकों को बेचा जाता है, तो चाय की पत्तियों जैसी वही वस्तुएँ अंतिम उत्पाद नहीं कहलाएँगी। उनकी गणना यहाँ आगत के रूप में की जाएगी, क्योंकि इससे आर्थिक मूल्य जुड़ जाता है। अत: किसी वस्तु का अंतिम उत्पाद होना वस्तु की प्रकृति पर निर्भर न होकर उसके आर्थिक उपयोग पर निर्भर करता है।

अंतर का आधार (Basis of difference)	उपभोक्ता/उपभोग वस्तुएँ (Consumer/Consumption Goods)	पूँजीगत वस्तुएँ (Capital Goods)
परिभाषा (Definition)	उपभोग वस्तुएँ, वे वस्तुएँ हैं, जो उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम रूप से उपयोग की जाती हैं। इनका उपयोग भविष्य में उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है।	पूँजीगत वस्तुएँ, वे वस्तुएँ हैं, जिनका भविष्य में उत्पादन हेतु उपयोग किया जाता है।
उद्देश्य (Purpose)	उपभोक्ता वस्तुओं को व्यक्तिगत उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ख़रीदा जाता है, जो खपत को बनाए रखता है।	पूँजीगत वस्तुएँ उपभोग वस्तुओं के विनिर्माण के लिए ख़रीदी जाती हैं।
मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि (Satisfaction of human Wants)	ये प्रत्यक्ष रूप से मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, इसलिए ये एक प्रत्यक्ष माँग के रूप में होते हैं।	ये अप्रत्यक्ष रूप से मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और इसलिए ये एक व्युत्पन्न माँग (Derived demand) के रूप में होते हैं।
रूपांतरण (Transformation)	उत्पादन या उपभोग की प्रक्रिया में इनका रूपांतरण हो भी सकता है और नहीं भी।	उत्पादन की प्रक्रिया में इनका रूपांतरण नहीं होता है।
लक्षित बाज़ार (Target Market)	उपभोक्ता	उत्पादक
माँग (Demand)	उपभोक्ता वस्तुओं की माँग अधिक होती है।	पूँजीगत वस्तुओं की माँग तुलनात्मक रूप से कम होती है।
मूल्य निर्धारण (Pricing)	तुलनात्मक रूप से सस्ता होता है।	उपभोग की वस्तुओं की तुलना में महँगा होता है।
उत्पादन क्षमता पर प्रभाव (Impact on Production Capacity)	श्रम उत्पादक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है।	श्रम और पूँजी उत्पादक क्षमता दोनों को बढ़ाने में मदद करता है।
अपेक्षित जीवन-काल (Expected Life)	सामान्यत: सीमित (फ़ास्ट मूविंग कंज़्यूमर गुड्स- FMCG के संदर्भ में)।	जीवनकाल में एक से अधिक उत्पादक चक्र शामिल होते हैं। ये टूट-फूट या मूल्य ह्रास (Depreciation) की प्रक्रिया से गुज़रते हैं और इसलिए इनके प्रतिस्थापन (Replacement) तथा मरम्मत (Repairing) की आवश्यकता होती है।
प्रकार (Types)	• **टिकाऊ वस्तुएँ:** ऐसी वस्तुएँ, जिनका दीर्घावधि तक बार-बार प्रयोग किया जा सकता है। • **गैर-टिकाऊ वस्तुएँ:** उपभोग के कार्य में इनका एक ही बार प्रयोग किया जाता है। • सेवाएँ।	
उदाहरण (Examples)	टेलीविज़न सेट, मोबाइल फ़ोन, दूध, फल इत्यादि।	मशीनरी, भवन, फ़र्नीचर इत्यादि।

1.4 अर्थशास्त्र का अध्ययन (Study of Economics)

अर्थशास्त्र के अध्ययन को व्यष्टि अर्थशास्त्र (Microeconomics) और समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics) में उप-वर्गीकृत किया जा सकता है।

- **व्यष्टि अर्थशास्त्र** (Microeconomics)**:** यह संसाधनों की कमी और सरकारी हस्तक्षेप को देखते हुए संसाधनों के आवंटन के संबंध में व्यक्तिगत या व्यावसायिक निर्णय के अर्थशास्त्र का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपूर्ति और माँग के बीच संबंध, वस्तुओं और सेवाओं की क़ीमत तथा मज़दूरी, रोज़गार, मुद्रास्फीति के बीच संबंध जैसी अवधारणाएँ शामिल हैं।
- **समष्टि अर्थशास्त्र** (Macroeconomics)**:** यह विशिष्ट व्यक्तिगत बाज़ारों या आर्थिक गतिविधियों के बजाय संपूर्ण अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और संरचना का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति (Inflation), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (International trade), बेरोज़गारी (Unemployment) और राष्ट्रीय खपत (National consumption) तथा उत्पादन, बचत एवं सामान्य मूल्य स्तर जैसी अवधारणाएँ शामिल हैं।

1.5 अर्थव्यवस्था में विचारधाराएँ (Schools of Economic Thought)

आर्थिक विचारधाराएँ सामान्यत: दो प्रकार के दृष्टिकोणों- पारंपरिक/शास्त्रीय (Classical) और कीन्सियन में विभाजित हैं।

- पारंपरिक/शास्त्रीय दृष्टिकोण (Classical view) के अनुसार मुक्त बाज़ार, संसाधनों को आवंटित करने का सर्वोत्तम तरीका है। सरकार की भूमिका निष्पक्ष और सख़्त विनियामक (Strict Regulator) तक सीमित होनी चाहिए।
- इसके विपरीत, कीन्सियन दृष्टिकोण (Keynesian approach) के अंतर्गत यह माना जाता है कि बाज़ार अपने आप से संसाधनों को आवंटित करने में सक्षम नहीं होते हैं। सरकारों

को समय-समय पर आर्थिक संवृद्धि एवं विकास के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और सक्रिय रूप से संसाधनों को कुशलतापूर्वक पुनः आवंटित (Reallocate) करना चाहिए।

1.6 अर्थव्यवस्था के प्रकार (Types of Economy)

1.6.1 राज्य की भूमिका के संदर्भ में (In Terms of Role of State)

मानव जाति के सभ्य इतिहास को प्रभावित करने वाला सबसे विवादास्पद मुद्दा यह रहा है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया को कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए? क्या उत्पादन की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य/सरकार की होनी चाहिए या इसे पूरी तरह से निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया जाना चाहिए?

प्रत्येक समाज को आर्थिक प्रणाली के प्रकार को निर्धारित करने वाले तीन प्रश्नों के उत्तर देना होता है:

- देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाना चाहिए?
- वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाना चाहिए? क्या उत्पादकों को उत्पादन के लिए अधिक मानव श्रम या अधिक पूँजी (मशीनों) का उपयोग करना चाहिए?

अर्थव्यवस्था के प्रकार	क्या उत्पादित होता है	इसका उत्पादन कैसे किया जाता है	इसका वितरण कैसे किया जाता है
पूँजीवादी/बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ (उदाहरण: यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा)	लोगों की आवश्यकता के अनुसार ऐसी वस्तुएँ, जिन्हें वे ख़रीदने एवं बेचने के लिए तैयार हैं।	व्यवसायी उत्पादन के सबसे कुशल (विधिक रूप से मान्य) तरीकों का निर्धारण करते हैं।	यह इस बात से निर्धारित होता है कि कोई व्यक्ति कितना भुगतान करने में सक्षम या तैयार है।
समाजवादी/नियंत्रित (कमांड) अर्थव्यवस्थाएँ (उदाहरण-सोवियत संघ, क्यूबा)	सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है।	सरकार का निर्णय प्रभावी होता है।	सरकार सामान्यतः वर्ग/जाति/लिंग के आधार पर सभी के लिए समानता सृजित करने का निर्णय लेती है।

- लोगों के बीच वस्तुओं और सेवाओं को कैसे वितरित किया जाना चाहिए?

इन तीन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर, आर्थिक प्रणालियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

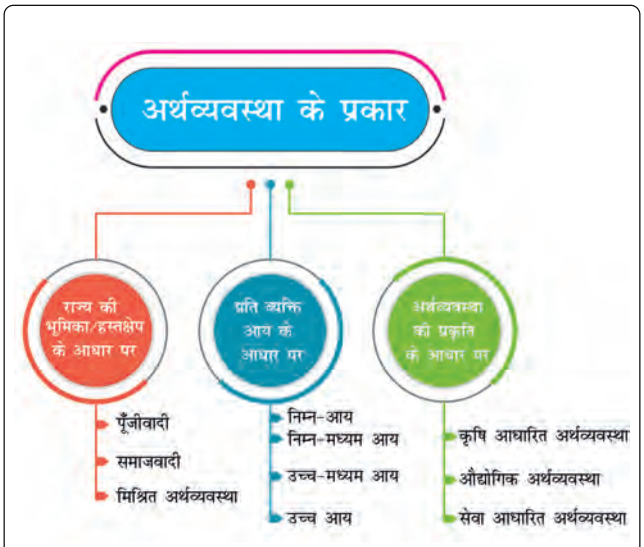

A. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy)

अर्थव्यवस्था के पूँजीवादी रूप की उत्पत्ति एडम स्मिथ की प्रसिद्ध रचना- एन इन्क्वारी इन टू द नेचर एंड कॉज़ेज़ ऑफ़ द वेल्थ ऑफ़ नेशन्स (An Enquiry into the nature and the causes of the wealth of nations) (1776) में हुई थी। उन्होंने 'अहस्तक्षेप की नीति (Laissez faire)', अर्थात् मुक्त व्यापार/राज्य या सरकार द्वारा अहस्तक्षेप पर बल दिया।

क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस क़ीमत पर बेचना है, इसका निर्णय बाज़ार द्वारा लिया जाना चाहिए। इस प्रणाली में निजी उद्यमों (Private enterprises) की भूमिका प्रभावी होती है और राज्य की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है।

- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में बाज़ार मूल्य आपूर्ति और माँग के नियम के माध्यम से निर्धारित होता है।
- उदाहरण के लिए, जब कॉफ़ी की माँग बढ़ती है, तो लाभ के लिए प्रयासरत व्यवसायी अपने लाभ को बढ़ाने के लिए क़ीमतों को बढ़ा देगा। यदि, उसी समय, चाय की माँग कम हो जाती है, तो उत्पादकों को इसे कम क़ीमतों पर बेचना पड़ेगा और फलस्वरूप कुल उत्पादन में गिरावट आएगी।
- यदि श्रम, पूँजी की तुलना में सस्ता है, तो उत्पादन के अधिक श्रम-गहन तरीकों (Labour-intensive methods) का उपयोग किया जाएगा।
- एक पूँजीवादी समाज में, उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच इस आधार पर वितरित नहीं किया जाता है कि लोगों की आवश्यकता क्या है, बल्कि इस आधार पर वितरित किया जाता है कि लोग क्या ख़रीद सकते हैं और क्या ख़रीदने के इच्छुक हैं।

  इसका तात्पर्य है कि एक रोगी व्यक्ति यदि औषधि ख़रीदने में सक्षम होगा तभी आवश्यक औषधि का उपयोग कर सकेगा। यदि वह औषधि का ख़र्च वहन नहीं कर सकता है, तो वह इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा, भले ही उसे औषधि की तत्काल आवश्यकता हो।

B. समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy)

अर्थव्यवस्था का समाजवादी रूप जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स (1818-83) द्वारा प्रस्तावित ऐतिहासिक परिवर्तन के विचारों में निहित था। विशेष रूप से, इस तरह की आर्थिक प्रणाली पहली बार बोल्शेविक क्रांति (1917) के बाद पूर्ववर्ती सोवियत संघ में लागू की गई और इसके बाद चीनी जनवादी गणराज्य/पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (1949) में इन नीतियों को व्यावहारिक आकार प्रदान किया गया।

एक वास्तविक समाजवादी प्रणाली में, निर्गत (Output) और मूल्य निर्धारण स्तरों को निर्धारित करना सरकार की भूमिका है। इसमें उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के साथ इन निर्णयों में तादात्मय स्थापित करना एक प्रकार की चुनौती है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था उपरोक्त तीनों प्रश्नों के उत्तर भिन्न तरीके से देती है:

- **पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से भिन्नता** (Distinction from Capitalist Economy): सैद्धांतिक रूप में पूँजीवाद के विपरीत, समाजवाद के तहत वितरण इस तथ्य पर आधारित होता है कि लोगों को क्या चाहिए, न कि वे क्या ख़रीद सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक समाजवादी राष्ट्र उन नागरिकों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। एक कठोर समाजवादी राज्य में कोई निजी संपत्ति नहीं होती है, क्योंकि समग्र संसाधन राज्य के स्वामित्व क्षेत्र में आते हैं।
- समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों के सामूहिक स्वामित्व (संपत्ति और परिसंपत्ति) पर बल दिया जाता है और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को संचालित करने में राज्य की एक बड़ी भूमिका अपेक्षित होती है।
- **साम्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में भिन्नता** (Distinction between Communist and Socialist Economy): मौलिक रूप से अलग होने के बावजूद, समाजवाद और साम्यवाद की अवधारणा को प्राय: एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है।
- साम्यवाद में सभी आर्थिक संसाधन सार्वजनिक रूप से सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। व्यक्तियों के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होती है।

  समाजवाद में व्यक्ति निजी संपत्ति के स्वामी हो सकते हैं, लेकिन सभी औद्योगिक और उत्पादन के साधन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के स्वामित्व तथा प्रबंधन में होते हैं।
- साम्यवाद में वर्ग विभेद समाप्त हो जाता है। एक श्रमिक के दूसरे की तुलना में अधिक आय अर्जन की संभावना न के बराबर होती है।

  समाजवाद में वर्ग उपस्थित होते हैं, लेकिन उनके बीच अंतराल बहुत कम हो जाता है। कुछ लोगों के पास दूसरों की तुलना में अधिक धनार्जन संभव होता है।

C. मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)

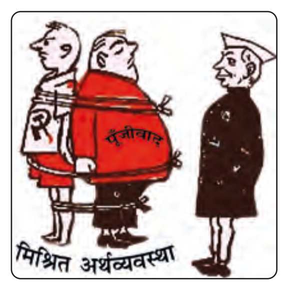

यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है, जिसमें पूँजीवाद और समाजवाद, दोनों की विशेषताएँ होती हैं। एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली पूँजी के उपयोग में निजी आर्थिक स्वतंत्रता की अनुमति देती है। इसके साथ ही जब भी आवश्यकता हो, तो सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारों को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने अनुमति होती है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था 'खुले व्यापार की निति' पर आधारित नहीं होती है तथा सरकार संसाधनों के उपयोग की योजना बनाने का कार्य करती है और इसके साथ ही निजी क्षेत्र के व्यवसायों पर नियंत्रण रख सकती है।

उदाहरण के लिए, सरकारें निजी क्षेत्र पर कर लगाकर और सामाजिक हितों को बढ़ावा देने के लिए संगृहीत करों का उपयोग करके धन का पुनर्वितरण कर सकती हैं।

1.6.2 भारत द्वारा अपनाया गया मॉडल (Model Adopted by India)

भारत की स्वतंत्रता के बाद नीति निर्माताओं को यह तय करना था कि हमारे राष्ट्र के लिए सबसे उपयुक्त आर्थिक प्रणाली का प्रकार क्या होना चाहिए, जो कुछ विशेष वर्ग के बजाय सभी वर्गों के कल्याण को बढ़ावा दे।

विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियों के बीच जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से सबसे अधिक प्रभावित थे। यद्यपि, वह पूर्व सोवियत

संघ में स्थापित समाजवाद के ऐसे प्रकार के पक्ष में नहीं थे, जहाँ उत्पादन के सभी साधन, अर्थात् देश के सभी कारखाने और खेत, सरकार के स्वामित्व में थे तथा किसी निजी संपत्ति की उपस्थिति नहीं थी। भारत जैसे लोकतंत्र में यह संभव नहीं था कि पूर्व सोवियत संघ की भाँति सरकार नागरिकों की भूमि और अन्य संपत्तियों के स्वामित्व प्रारूप (Ownership pattern) को पूरी तरह से बदल दे, क्योंकि इससे औद्योगिक वर्गों के बीच अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती, जिसके फलस्वरूप भारत की संवृद्धि और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता।

नीति निर्माताओं को इन समस्याओं का उत्तर मिश्रित आर्थिक प्रणाली में मिला, जिसमें उन्होंने समाजवाद की कमियों को हटाकर उसकी सर्वोत्तम विशेषताओं को शामिल किया। इस दृष्टि से, भारत एक मज़बूत सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी संपत्ति और लोकतंत्र के साथ एक समाजवादी समाज होगा; सरकार अर्थव्यवस्था का नियोजन करेगी और निजी क्षेत्र को नियोजन प्रयास का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि आधुनिकीकरण की परियोजनाओं के पूर्ण होने की अवधि लंबी थी। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं में बड़ी पूँजी की आवश्यकता थी और इसमें आर्थिक जोखिम भी था, जिसको नवजात निजी क्षेत्र नहीं उठा सकता था। अत: स्वतंत्रता के बाद, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में, कुछ बुनियादी और महत्त्वपूर्ण अवसंरचनात्मक आर्थिक ज़िम्मेदारियों को सरकारों (केंद्र और राज्य) द्वारा उठाया गया और बाकी आर्थिक गतिविधियों को निजी उद्यम, अर्थात् बाज़ार पर छोड़ दिया गया था।

लेकिन वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में जब देश ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की, तो प्रचलित राज्य-बाज़ार के अंतर्संबंधों को पुन:परिभाषित किया गया और मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक नया रूप अपनाया जाने लगा।

- भारत में पुन:परिभाषित मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाज़ार अर्थव्यवस्था को अधिक समर्थन दिया गया।
- पूर्णत: सरकारी एकाधिकार के अधीन कई आर्थिक भूमिकाएँ, जैसे- दूरसंचार, विद्युत, सड़क, तेल और प्राकृतिक गैस इत्यादि में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया।
- साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल जैसे सामाजिक क्षेत्रकों पर राज्य द्वारा अतिरिक्त बल दिया गया ताकि राज्य के कल्याणकारी दायित्व के साथ निजी क्षेत्र के लाभ माँगने वाले हित के बीच संतुलन बनाया जा सके।

भारत की आर्थिक प्रणाली वर्ष 1991 से पहले के वर्षों में एक मिश्रित प्रणाली थी। वर्ष 1991 के बाद के वर्षों में राज्य-बाज़ार मिश्रित संरचना में बदलाव आया है। (भारत ने मिश्रित आर्थिक प्रणाली को क्यों अपनाया, इनके विस्तृत कारणों को जानने के लिए सामाजिक-आर्थिक योजना देखें)।

1.6.3 प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में (In Terms of Per Capita Income)

विश्व बैंक अर्थव्यवस्थाओं को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) के आधार पर वर्गीकृत करता है। श्रेणियाँ नीचे दी गई हैं:

अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण (वार्षिक)	
अर्थव्यवस्था	प्रति व्यक्ति GNI (2016)
निम्न आय	$ 1,046 या उससे कम
निम्न-मध्यम आय	$ 1,046 और $ 4,095 के मध्य
उच्च-मध्यम आय	$ 4,096 और $ 12,695 के मध्य
उच्च आय	$ 12,696 या अधिक

निम्न आय और निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को सामान्यत: विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (Developing Economies) के रूप में जाना जाता है। ऊपरी मध्य-आय और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक के अनुसार भारत को 1900 डॉलर प्रति व्यक्ति GNI के साथ निम्न-मध्यम आय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

1.7 संरचनात्मक संघटक (Structural Composition)

देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, अर्थात् कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र द्वारा किया गया योगदान अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक संघटक बनाता है।

A. प्राथमिक क्षेत्रक (Primary Sector)

प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों से कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल है। इसलिए, इसे कभी-कभी निष्कर्षण क्षेत्र (Extraction Sector) के रूप में भी जाना जाता है। इस निष्कर्षण के परिणामस्वरूप कच्चे माल और बुनियादी खाद्य पदार्थ, जैसे कोयला, लकड़ी, लोहा और मकई (मक्का) प्राप्त होते हैं। चूँकि हमें अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, दुग्ध क्षेत्र (Dairy), वानिकी (Forestry), मत्स्यन से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक गतिविधि में लगे लोगों को उनके कार्य की बाह्य प्रकृति के कारण रेड कॉलर श्रमिक (Red collar workers) कहा जाता है।

B. द्वितीयक क्षेत्रक (Secondary Sector)

द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल को तैयार करना या विनिर्मित माल में रूपांतरित करना शामिल है। इस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing sector) भी कहा जाता है। चूँकि विनिर्माण कार्य उद्योगों द्वारा किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल, वस्त्र उद्योग इत्यादि। द्वितीयक गतिविधि में संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर श्रमिक (Blue collar workers) कहा जाता है।

विनिर्माण क्षेत्र के उदाहरण:

- बर्तन बनाने व शिल्पकारी वाली लघु इकाइयाँ;
- वस्त्रों का उत्पादन करने वाली मिलें;
- इस्पात, रसायन, प्लास्टिक और कार का उत्पादन करने वाले कारखाने;
- खाद्य-पदार्थ उत्पादन जैसे कि शराब निर्माण में मद्यनिर्माणशाला संयंत्र (Brewing plants) और खाद्य प्रसंस्करण;
- तेल रिफ़ाइनरी।

C. तृतीयक क्षेत्रक (Tertiary Sector)

सेवा क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के संवर्धन में मदद करता है। यह उपभोक्ताओं और व्यवसायों को महत्त्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करता है। इसमें विनिर्मित वस्तुओं की खुदरा बिक्री शामिल है। यह बीमा और बैंकिंग जैसी सेवाएँ भी प्रदान करता है। यह द्वितीयक क्षेत्र से निर्मित वस्तुओं में मूल्यवर्धन करता है। इस क्षेत्रक के रोज़गार को व्हाइट कॉलर रोज़गार कहा जाता है।

क्षेत्रक	सकल घरेलू उत्पाद में योगदान	नियोजित कार्यबल का अनुपात
कृषि	17%	53%
उद्योग	29%	22%
सेवाएँ	54%	25%

D. चतुर्थक क्षेत्रक (Quaternary Sector)

चतुर्थक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का बौद्धिक पक्ष (Intellectual aspect) कहा जाता है। इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का विकास और अनुसंधान तथा विकास शामिल हैं। इसे ज्ञान का क्षेत्र भी कहा जाता है। यह वह प्रक्रिया है, जो उद्यमियों को बेहतर विनिर्माण प्रक्रियाओं का आविष्कार (नवाचार) करने और अर्थव्यवस्था में दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम बनाती है। प्रौद्योगिकी और सूचना के इस विकास के बिना, आर्थिक विकास धीमा या अस्तित्वहीन होगा।

E. पंचम क्षेत्रक (Quinary Sector)

पंचम क्षेत्रक में किसी समाज या अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने का उच्चतम स्तर शामिल होता है। इस क्षेत्र में सरकार, विज्ञान, विश्वविद्यालयों, गैर-लाभकारी, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और मीडिया जैसे क्षेत्रों के शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं। इसमें पुलिस और अग्निशमन विभाग भी शामिल हैं, जो लाभकारी उद्यमों के विपरीत सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करते हैं।

इनमें वे सेवाएँ शामिल हैं, जो नवाचार, सृजन पुनर्व्यवस्था (Creation rearrangement) और विचारों की व्याख्या (Interpretation of ideas) पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इस श्रेणी के तहत पेशे को गोल्ड कॉलर पेशेवर (Gold collar Professional) कहा जाता है। अर्थशास्त्री कभी-कभी पंचम क्षेत्र में घरेलू गतिविधियों (परिवार के सदस्य या आश्रित द्वारा घर में किए गए कार्य) को भी शामिल करते हैं। ये गतिविधियाँ सामान्यतः मौद्रिक राशि से नहीं मापी जाती हैं, लेकिन नि:शुल्क सेवाएँ प्रदान करके अर्थव्यवस्था में योगदान करती हैं, जैसे कि बाल-देखभाल या गृह देखभाल (Housekeeping)।

1.8 भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Transformation of Indian Economy)

एक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन सामान्यतः उत्पादन, रोज़गार की 'खंडीय संरचना' (Sectoral Structure) तथा उत्पादन एवं रोज़गार की ग्रामीण-शहरी संरचना में परिवर्तन से जुड़ा होता है।

जैसे-जैसे कोई देश विकसित होता है, वह संरचनात्मक परिवर्तन (रूपांतरण) से गुज़रता है। किसी देश की प्राकृतिक आर्थिक प्रगति कृषि अर्थव्यवस्था से होकर औद्योगिक अर्थव्यवस्था के माध्यम से सेवा अर्थव्यवस्था तक जाती है। लेकिन भारत की विकास गाथा अलग रही है और भारत कृषि अर्थव्यवस्था से एक सेवा अर्थव्यवस्था में छलांग लगा रहा है।

1.8.1 विशिष्ट संरचनात्मक परिवर्तन (Peculiar Structural Changes)

- भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा वर्ष 1960 के दशक की शुरुआत में 40% से अधिक गिरकर वर्ष 2000 के दशक के अंत तक लगभग 17% हो गया।

- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जैसे-जैसे आर्थिक विकास दर बढ़ी, कृषि हिस्सेदारी में गिरावट की दर तीव्र हो गई।
- समग्र रूप से औद्योगिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी वर्ष 1960 में लगभग 20% से बढ़कर वर्ष 2009 में लगभग 28% हो गई, जबकि अकेले विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा निराशाजनक रूप से पूरी अवधि के दौरान लगभग 15% रहा, जो शिथिल संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत है।
- वर्ष 1990 तक सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 40.59 प्रतिशत थी, जो कृषि या उद्योग की हिस्सेदारी से अधिक थी, जैसा कि हम विकसित देशों में पाते हैं। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि की यह घटना वर्ष 1991 के बाद की अवधि में तीव्र हो गई थी।
- वर्तमान में, सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% से अधिक योगदान के साथ अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े और सबसे तीव्रता से बढ़ते क्षेत्र के रूप में उभरा है।
- सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सेवा क्षेत्र के बढ़ते योगदान को भारतीय अर्थव्यवस्था का बढ़ता तृतीयकीकरण (Tertiarization) कहा जाता है।

1.8.2 भारतीय अर्थव्यवस्था के असममित संरचनात्मक रूपांतरण के कारण (Reasons for Asymmetric Structural Transformation of Indian Economy)

भारतीय अर्थव्यवस्था के असममित संरचनात्मक परिवर्तन (Asymmetrical Structural changes) का कारण तृतीयक क्षेत्र में तीव्र वृद्धि और द्वितीयक क्षेत्र में धीमी वृद्धि है।

A. द्वितीयक क्षेत्र में धीमी वृद्धि के कारण (Reasons for Slow Growth in Secondary Sector)

1. **कठोर श्रम कानून** (Stringent Labor Laws)**:** भारत में श्रम कानून बेहद जटिल हैं। उदाहरण के लिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में प्रावधान है कि यदि 100 श्रमिकों या उससे अधिक का कोई विनिर्माण प्रतिष्ठान (Manufacturing Firm) है, तो किसी भी परिस्थिति में उनमें से किसी भी श्रमिक को बर्ख़ास्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि प्रतिष्ठान (फ़र्म) को सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त न हो, जो शायद ही कभी दिया जाता है। कानून का पालन करना आवश्यक है, भले ही उद्योग दिवालिया हो रहा हो। इस प्रकार निवेशक इस क्षेत्र में प्रवेश करने के कम इच्छुक होते हैं।
2. **अपर्याप्त कुशल कार्यबल** (Inadequate Skilled Workforce)**:** विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने के लिए, आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण के साथ एक शिक्षित कार्यबल की आवश्यकता होती है। भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर करने की आवश्यकता है।
3. **बुनियादी ढाँचा/अवसंरचना** (Basic Infrastructure)**:** भारत में विकसित देशों की तुलना में सड़क, संपर्कता (Connectivity) का विकास मंद है तथा परिवहन महँगा है, जो उद्योगों के विकास के लिए एक बड़ा बाधक है। निर्बाध विद्युत आपूर्ति एक अन्य चुनौती है।
4. **लघु आकार** (Small Size)**:** लघु उद्यम, आकार में छोटे होने के कारण, कम उत्पादकता से प्रभावित रहते हैं, जिससे उनका लाभकारी बने रहना चुनौतीपूर्ण होता है।
5. **अनुसंधान एवं विकास पर कम ख़र्च** (Low Spending on R & D)**:** वर्तमान में, भारत अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7% ख़र्च करता है, जो अन्य विकसित देशों की तुलना में अत्यंत कम है। यह इस क्षेत्र विकास, नवाचार और संवृद्धि को सीमित करता है।

B. तृतीयक क्षेत्र में तीव्र वृद्धि के कारण (Reasons for Rapid Increase in Tertiary Sector)

1. सूचना और ज्ञान अर्थव्यवस्था के आगमन के पश्चात् सेवाओं में उच्च उत्पादकता के विकास को बढ़ावा मिला। इसका श्रेय अच्छी तरह से शिक्षित और धाराप्रवाह अंग्रेज़ी बोलने वाले मानव संसाधनों को दिया जाता है। इससे सॉफ़्टवेयर और आईटीईएस महत्त्वपूर्ण सेवा निर्यात में भारत को सफलता प्राप्त हुई है।
2. सार्वजनिक सेवाओं में विकास तीव्र होता है, जहाँ राष्ट्रीय सरकार की समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में योजना और उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
3. सेवा क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में लचीला बुनियादी ढाँचा, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, वित्त, परिवहन और संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि शामिल हैं। विकास की तत्काल आवश्यकता इन सेवाओं द्वारा प्रदान किए गए सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढाँचे का उचित विस्तार है।
4. बढ़ते शहरीकरण को एक अन्य कारक के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि यह संचार, सार्वजनिक उपयोगिताओं और वितरण सेवाओं जैसे बुनियादी ढाँचे की सेवाओं की माँग में वृद्धि से निकटता से जुड़ा हुआ है।
5. पर्यटन अधिक-से-अधिक अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है, क्योंकि टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान का प्रसार किया जा रहा है, जिससे होटल, आवास जैसी विभिन्न सेवाओं को बढ़ावा मिल रहा है।
6. उपरोक्त संवृद्धि के साथ ही आधुनिक औद्योगिक संगठन की जटिलताओं से विनिर्माण उद्योग सेवा उन्मुख हो गए हैं। यह लेखांकन, वित्त, विधिक् सेवाओं (Legal Services), विज्ञापन, विपणन इत्यादि की बढ़ती गतिविधियों में परिलक्षित हुआ है।

विगत् वर्षों की प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों का अभ्यास कीजिए

1. निम्नलिखित में कौन-कौन-से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक (रियल सेक्टर) का निर्माण करते हैं?
   1. किसानों का अपनी फ़सलें काटना (Harvesting their crops)
   2. कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना
   3. किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना
   4. किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया-अंकित मूल्य के बॉण्ड (Rupee Denominated Bonds) जारी करना

   नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

   (a) केवल 1 और 2
   (b) केवल 2, 3 और 4
   (c) केवल 1, 3 और 4
   (d) 1, 2, 3 और 4

   (2022)

उत्तर. (a)

2. किसी भी देश के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूँजी (Social Capital) के भाग के रूप में समझा जाएगा?

   (a) जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात
   (b) इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक
   (c) कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप (Size)
   (d) समाज में आपसी भरोसे (Trust) और सामंजस्य (Harmony) का स्तर

   (2019)

उत्तर. (d)

अध्याय

2

व्यष्टि अर्थशास्त्र (Microeconomics)

2.1 मूल अवधारणाएँ (Basic Concepts)

व्यष्टि अर्थशास्त्र, विकल्पों के चयन तथा उत्पादन के कारकों में बदलाव के दौरान आर्थिक प्रवृत्तियों तथा व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन है। व्यक्तिगत इकाइओं को प्राय: व्यष्टि-आर्थिक उप-समूहों (Micro-economic subgroups), जैसे ख़रीदारों, विक्रेताओं तथा व्यवसाय मालिकों (Business owners) में विभाजित किया जाता है।

2.1.1 चयन का सिद्धांत (Theory of Choice)

चयन का सिद्धांत माँग एवं आपूर्ति, दोनों स्तरों पर कार्य करता है।

आपूर्ति पक्ष (Supply side): आपूर्ति पक्ष उत्पादन फलन (Production function) द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक उत्पादन फलन इस तथ्य को व्यक्त करता है कि किसी फर्म (प्रतिष्ठान) का उत्पादन उसके द्वारा नियोजित 'आगत' (Input) की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि फर्म अधिकतम 'लाभ' (अपने निर्गत के बिक्री मूल्य तथा आगत की लागत के बीच अंतर के रूप में परिभाषित) प्राप्त करना चाहती है, तो यह आगत के उस संयोजन का चयन करेगी, जो इसके ख़र्चों को कम करता है तथा राजस्व को अधिकतम करता है।

माँग पक्ष (Demand side): माँग पक्ष उपयोगिता फलन (Utility function) द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक परिवार की एक निश्चित "रुचि (Tastes)" होती है, जिसे "उपयोगिता फलन" की शृंखला में व्यक्त किया जा सकता है। एक उपयोगिता फलन (उत्पादन फलन के समान एक समीकरण) दर्शाता है कि उपभोग से परिवारों को मिलने वाली प्रसन्नता या संतुष्टि उनके द्वारा ख़रीदे जाने वाले उत्पादों और इस बात पर निर्भर करेगी कि वे इन उत्पादों का उपभोग कैसे करते हैं।

यह मानना आवश्यक है कि परिवार संतुष्टि को अधिकतम करना चाहते हैं तथा वे अपनी आय को उपलब्ध उपभोक्ता वस्तुओं के बीच इस तरह से वितरित करेंगे कि उपभोग से सर्वाधिक संभव "उपयोगिता" प्राप्त हो। सिद्धांतत: उनकी आय निश्चित मानी जाती है।

आर्थिक सिद्धांत में, उत्पादन फलन उत्पाद बाज़ारों में फर्मों के लिए आपूर्ति वक्रों (उत्पाद की क़ीमत और मात्रा जिसके लिए विक्रेता तैयार तथा सक्षम है, के बीच संबंधों का आलेखीय निरूपण) तथा कारक बाज़ारों में फर्मों के लिए माँग वक्र (उत्पाद की क़ीमत और माँग किए गए उत्पाद की मात्रा के बीच संबंध का आलेखीय निरूपण) की गणना में योगदान देता है।

ये सभी माँग एवं आपूर्ति वक्र माँग तथा आपूर्ति की मात्रा को क़ीमतों के एक फलन के रूप में व्यक्त करते हैं, इसलिए नहीं कि क़ीमत अकेले आर्थिक व्यवहार को निर्धारित करती है, बल्कि इसलिए कि इसका उद्देश्य मूल्य निर्धारण (Price determination) के सिद्धांत पर पहुँचना है।

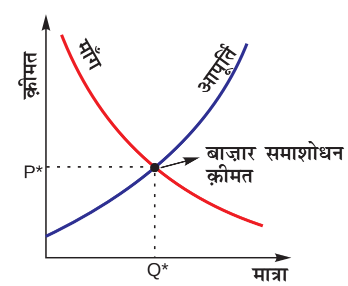

संतुलन/बाज़ार समाशोधन क़ीमत

महत्त्वपूर्ण बिंदु यह है कि अधिकांश 'माँग वक्र' (Demand Curves) ऋणात्मक रूप से झुके हुए/ढलानदार (Inclined/sloping) होते हैं (इसका अर्थ है कि उपभोक्ता की माँग एवं क़ीमत के बीच एक व्युत्क्रम संबंध होता है, इसलिए क़ीमत बढ़ने पर उपभोक्ता कम माँग करते हैं)। जबकि अधिकांश आपूर्ति वक्र धनात्मक रूप से झुके हुए/ढलानदार होते हैं (इसका तात्पर्य है कि आपूर्ति एवं क़ीमत के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसलिए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उच्च क़ीमतों पर अधिक उत्पादन करने की संभावना होती है)। बाज़ार में प्रतिभागी उस क़ीमत की ओर जाएँगे, जिस पर दो वक्र प्रतिच्छेद (Intersect) करते हैं; इस क़ीमत को "साम्य" क़ीमत (Equilibrium, price) या "बाज़ार-समाशोधन" क़ीमत (Market-clearing, price) कहा जाता है, क्योंकि यह एकमात्र क़ीमत है, जिस पर आपूर्ति एवं माँग समान होती है।

2.2 माँग (Demand)

2.2.1 माँग वक्र (Demand Curve)

माँग वक्र उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा तथा वस्तु की क़ीमत के बीच का संबंध है। स्वतंत्र चर (क़ीमत) को ऊर्ध्वाधर अक्ष (y-अक्ष) के साथ मापा जाता है तथा आश्रित चर (मात्रा) को क्षैतिज अक्ष (x-अक्ष) के साथ मापा जाता है। माँग वक्र प्रत्येक क़ीमत पर उपभोक्ता द्वारा माँगी गई मात्रा बताता है।

माँग वक्र बाएँ से दाएँ नीचे की ओर बढ़ेगा, जो माँग के नियम को व्यक्त करता है।

2.2.2 माँग का नियम (Law of Demand)

माँग का नियम कहता है कि अन्य कारकों के स्थिर (नियत) रहने पर, किसी भी वस्तु व सेवा की क़ीमत और मात्रा की माँग एक-दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित हैं। जब किसी उत्पाद की क़ीमत बढ़ती है, तो उत्पाद की माँग कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, यदि माँग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक स्थिर रहते हैं, तो क़ीमत अधिक होने पर माँग की मात्रा कम हो जाती है तथा क़ीमत कम होने पर माँग की मात्रा बढ़ जाती है।

नीचे दिया गया आरेख माँग के नियम को स्पष्ट रूप से समझाता है:

जैसे ही वस्तु की क़ीमत 5 रुपये से घटकर 2 रुपये हो जाती है, तो वस्तु की माँग की मात्रा 100 इकाई से बढ़कर 400 इकाई हो जाती है।

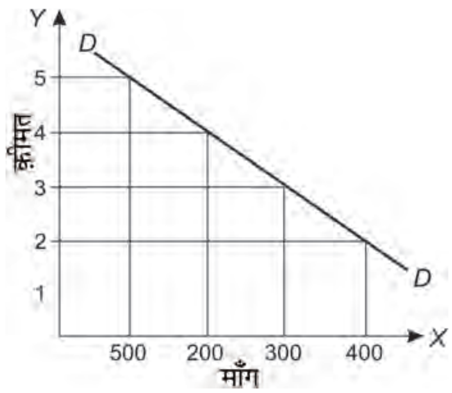

माँग वक्र

2.2.3 माँग के नियम की पूर्वधारणाएँ (Assumptions to the Law of Demand)

1. **उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है** (Income of the Consumer remains constant): यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, तो माँग के नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है, तो मूल्य वृद्धि के दौरान भी उपभोक्ता की माँग अप्रभावित रहेगी। इसके विपरीत यदि उपभोक्ता की आय गिरती है, तो क़ीमत गिरने के दौरान भी उपभोक्ता माँग कम होगी।

2. **उपभोक्ता की रुचि एवं प्राथमिकताएँ नहीं बदलतीं हैं** (Consumer Taste and Preferences do not change): यदि उत्पाद के संबंध में उपभोक्ता की रुचि, प्राथमिकता, रीति-रिवाज़ या आदत बदल जाती है (या तो उत्पाद के पक्ष में या उसके विरुद्ध) तो माँग का कानून अप्रभावी होगा।

3. **जनसंख्या का आकार तथा संरचना समान रहते हैं** (Size and Composition of Population remains same): कुल जनसंख्या का आकार तथा संरचना नहीं बदलनी चाहिए। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, वैसे-वैसे वस्तु की माँग भी बढ़ती है। 'जनसंख्या की जनसांख्यिकी' (Demography of population) में बदलाव के साथ, जनसंख्या की ज़रूरतें तथा माँगें बदल जाती हैं एवं इसी तरह वस्तु की माँग भी बदल जाती है।

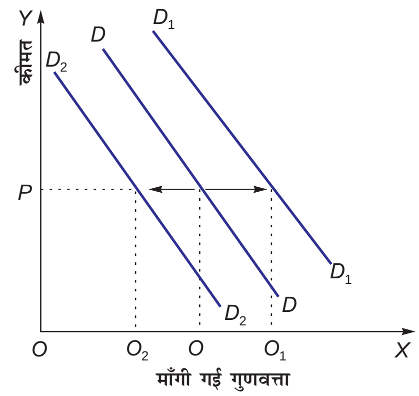

क़ीमत के अलावा अन्य चरों में परिवर्तन के कारण माँग वक्र में बदलाव

2.2.4 आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव (Income Effect and Substitution Effect)

'आय प्रभाव' आय में परिवर्तन के आधार पर उपभोग में परिवर्तन है। यदि उपभोक्ताओं की आय बढ़ती है, तो वे अधिक ख़र्च करते हैं और यदि उनकी आय घटती है, तो वे कम ख़र्च करते हैं। आय प्रभाव यह तय नहीं करता कि उपभोक्ता किस तरह की वस्तु ख़रीदेंगे। वे परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर कम मात्रा में अधिक महँगी वस्तुएँ या अधिक मात्रा में सस्ती वस्तुएँ ख़रीद सकते हैं।

'प्रतिस्थापन प्रभाव' एक आर्थिक गतिविधि है, इसमें कोई उपभोक्ता सापेक्ष क़ीमतों और व्यक्तिगत वित्त में परिवर्तन के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापित कर देता है। इसमें सस्ती वस्तुओं को महँगी वस्तुओं से या महँगी वस्तुओं को सस्ती वस्तुओं से प्रतिस्थापित करना शामिल है। प्रतिस्थापन प्रभाव का सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था के भीतर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह उपभोक्ता तथा उत्पादक के चयन को सीमित करता है।

आय प्रभाव किसी व्यक्ति या अर्थव्यवस्था की आय में परिवर्तन और किसी वस्तु या सेवा की माँग की मात्रा पर इसके प्रभाव को दर्शाता है। आय तथा माँग की मात्रा के बीच संबंध सकारात्मक है; जैसे-जैसे आय बढ़ती है, वैसे-वैसे माँग की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, तो वह व्यक्ति अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग करता है, जिससे खपत बढ़ जाती है।

2.2.5 माँग के नियम के अपवाद (Exceptions to the Law of Demand)

A. गिफ़िन वस्तु (Giffen Goods)

गिफ़िन (गिफ़ेन) वस्तु वह वस्तु है, जिसकी क़ीमत बढ़ने पर माँग बढ़ती है तथा क़ीमत घटने पर माँग घटती है। गिफ़िन वस्तु

में माँग वक्र का ढाल उर्ध्वगामी (Upward-sloping) होता है, जैसा कि आलेख में दिखाया गया है, जो माँग के मौलिक नियम के विपरीत है।

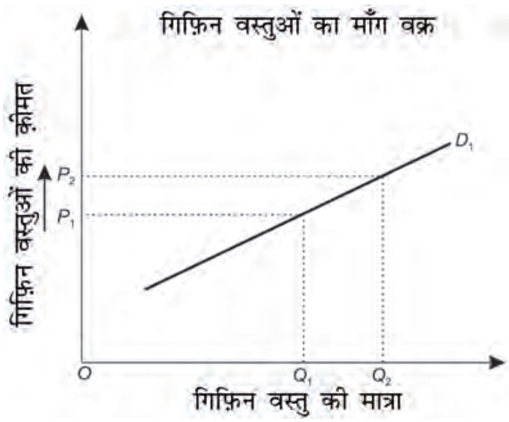

गिफ़िन वस्तुएँ सामान्य तौर पर निम्नकोटि की वस्तुएँ होती हैं, जिसके विकल्प आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव पर हावी हो जाता है। मुख्य खाद्य पदार्थ गिफ़िन वस्तु का एक उदाहरण हैं। इनका सेवन ग़रीबी में रहने वाले लोगों द्वारा केवल इस कारण से किया जाता है कि वे बेहतर खाद्य पदार्थ ख़रीदने में असमर्थ होते हैं। जैसे-जैसे बेहतर खाद्य पदार्थों की क़ीमत बढ़ती है, उपभोक्ता अधिक महँगे खाद्य पदार्थों के साथ अपने आहार को पूरित (पूरक) करने में असमर्थ होते जाते हैं, जिससे अन्य बेहतर खाद्य पदार्थों की क़ीमत के रूप में गिफ़िन वस्तु (मुख्य खाद्य पदार्थ) की माँग बढ़ जाती है।

B. वेबलेन वस्तु (Veblen Goods)

एक वस्तु, जिसकी विशिष्ट प्रकृति तथा 'प्रतिष्ठा के प्रतीक' (Status symbol) के रूप में आकर्षण के कारण क़ीमत बढ़ने पर माँग बढ़ती है, वेबलेन वस्तु कहलाती है। एक वेबलेन वस्तु में गिफ़िन वस्तु की तरह ही माँग वक्र का ढाल उर्ध्वगामी (Upward-sloping) होता है, जो सामान्य अधोगामी ढलान वाले माँग वक्र के विपरीत है।

हालाँकि, गिफ़िन वस्तु के विपरीत, जो एक निम्नकोटि का उत्पाद है, वेबलेन वस्तु सामान्य तौर पर एक उच्च गुणवत्ता वाला, प्रतिष्ठित उत्पाद (Coveted Product) है, जिसके विकल्प आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। साथ ही, गिफ़िन वस्तु के विपरीत, जिसमें उच्च माँग सीधे मूल्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है, वेबलेन वस्तु की माँग में वृद्धि उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताओं को दर्शाती है।

2.2.6 माँग की लोच (Demand Elasticity)

माँग की लोच से तात्पर्य है कि किसी वस्तु की माँग अन्य आर्थिक चरों, जैसे कि क़ीमत तथा उपभोक्ता आय में बदलाव के प्रति कितनी संवेदनशील है। माँग की लोच की गणना किसी वस्तु की माँग में प्रतिशत परिवर्तन को लेकर तथा इसे किसी अन्य आर्थिक चर में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करके की जाती है। किसी विशेष आर्थिक चर के लिए उच्च माँग लोच का तात्पर्य है कि उपभोक्ता इस चर जैसे कि क़ीमत या आय में परिवर्तन, के प्रति अधिक अनुक्रियाशील (Responsive) हैं।

लोचदार माँग

बेलोचदार माँग

- **केस 1:** माँग की लोच > 1, इसे लोचदार (Elastic) कहा जाता है, अर्थात् यह अन्य आर्थिक कारकों में परिवर्तन के प्रति आनुपातिक रूप से अधिक अनुक्रिया करता है। क़ीमत या आय में 1% परिवर्तन से माँग में 1% से अधिक परिवर्तन होता है।
- **केस 2:** माँग की लोच < 1, इसे बेलोचदार (Inelastic) कहा जाता है एवं माँग किसी अन्य चर में परिवर्तन के प्रति आनुपातिक रूप से कम अनुक्रिया करती है। क़ीमत या आय में 1% परिवर्तन से माँग में 1% से कम परिवर्तन होता है।

2.2.7 माँग की लोच के प्रकार (Types of Demand Elasticity)

A. प्रति लोच (Cross Elasticity)

संबंधित वस्तु की क़ीमत में परिवर्तन के प्रति किसी वस्तु की माँग की अनुक्रियाशीलता (Responsiveness) की माप को माँग की प्रति क़ीमत लोच कहा जाता है। इसे सदैव प्रतिशत के रूप में मापा जाता है।

उपभोग व्यवहार संबंधित होने के कारण, संबंधित वस्तु की क़ीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की माँग में परिवर्तन होता है। संबंधित

वस्तुएँ दो प्रकार की, अर्थात् स्थानापन्न (Substitutes) एवं पूरक (Complementary) होती हैं।

1. **स्थानापन्न वस्तुएँ** (Substitute Goods): स्थानापन्न वस्तुओं की माँग की प्रति लोच हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि यदि एक वस्तु की क़ीमत बढ़ती है, तो दूसरी वस्तु की माँग बढ़ जाती है।

   यदि दो वस्तुएँ चाय एवं कॉफी की तरह एक-दूसरे के लिए स्थानापन्न/विकल्प हैं, तो प्रति क़ीमत लोच धनात्मक होगी, अर्थात्, यदि कॉफी की क़ीमत बढ़ती है, तो चाय की माँग बढ़ जाती है।

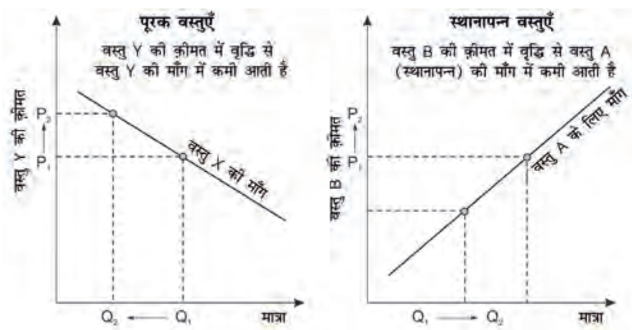

दो निकट पूरक वस्तुओं तथा स्थानापन्न वस्तुओं के बीच संबंध

2. **पूरक वस्तुएँ** (Complementary Goods): पूरक वस्तुओं की माँग की प्रति लोच ऋणात्मक होती है। जैसे-जैसे किसी वस्तु की क़ीमत बढ़ती है, उस वस्तु से निकटता से संबद्ध तथा उसके उपभोग के लिए आवश्यक वस्तु की खपत कम हो जाती है, क्योंकि मुख्य वस्तु की माँग भी कम हो जाती है।

   यदि वस्तुएँ प्रकृति में पूरक हैं, जैसे कलम एवं स्याही, तो प्रति लोच ऋणात्मक होगी, अर्थात् कलम की क़ीमत बढ़ने पर स्याही की माँग घट जाएगी या स्याही की क़ीमत बढ़ने पर कलम की माँग घट जाएगी।

B. माँग की क़ीमत लोच (Price Elasticity of Demand)

माँग की क़ीमत लोच किसी विशेष वस्तु की माँग की मात्रा में परिवर्तन तथा उसकी क़ीमत में परिवर्तन के बीच संबंध का माप है। जिस सीमा तक वस्तु की बढ़ती क़ीमत के कारण माँग में गिरावट आती है, उसे माँग की लोच या माँग की क़ीमत लोच कहा जाता है।

$$\text{माँग की क़ीमत लोच (PED)} = \frac{\text{माँग की मात्रा में \% परिवर्तन}}{\text{क़ीमत में \% परिवर्तन}}$$

यदि क़ीमत में एक छोटे से परिवर्तन के कारण माँग की मात्रा में बड़ा परिवर्तन होता है, तो उत्पाद को लोचदार (Elastic) (या मूल्य परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील) कहा जाता है। इसके विपरीत, यदि क़ीमत में बड़े परिवर्तन के कारण माँग की मात्रा में थोड़ा-सा परिवर्तन होता है, तो उत्पाद बेलोचदार (Inelastic) कहा जाता है। माँग की क़ीमत लोच किसी विशेष वस्तु के लिए क़ीमत में परिवर्तन के प्रति माँग की अनुक्रिया को मापती है।

- **केस 1:** यदि माँग की क़ीमत लोच = 0, तो माँग पूरी तरह से बेलोचदार है। जब उपभोक्ता किसी वस्तु की क़ीमत में वृद्धि या कमी पर कोई अनुक्रिया नहीं करते हैं, तथा माँग अपरिवर्तित रहती है, तो इसे पूर्णतः बेलोचदार (Perfectly inelastic) कहा जाता है (अर्थात्, क़ीमत बदलने पर माँग नहीं बदलती है)। उदाहरण के लिए: मधुमेह के रोगी के लिए इंसुलिन, अर्थात् आवश्यकता की वस्तुएँ।
- **केस 2:** यदि माँग की क़ीमत लोच <1, तो माँग अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है (यह तब होता है, जब माँग में प्रतिशत परिवर्तन क़ीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है)। उदाहरणार्थ: पेट्रोल, नमक, एकाधिकार (Monopoly) द्वारा उत्पादित वस्तुएँ आदि।
- **केस 3:** यदि माँग की क़ीमत लोच = 1, तो माँग इकाई लोचदार है (माँग में प्रतिशत परिवर्तन क़ीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर है)। ऐसा केवल उन वस्तुओं के साथ हो सकता है, जिनके लिए निकट स्थानापन्न या विकल्प हों, जैसे कपड़े के ब्रांड, उपभोक्ता वस्तुएँ आदि।
- **केस 4:** यदि माँग की क़ीमत लोच = ∞ (अनंत), तो माँग पूर्णतः लोचदार होती है (क़ीमत में परिवर्तन से माँग काफ़ी हद तक प्रभावित होती है)। उदाहरण के लिए: विलासिता की वस्तुएँ (Luxury Goods), निकटस्थ एवं बड़ी संख्या में स्थानापन्न वस्तुएँ।
- **केस 5:** यदि माँग की क़ीमत लोच > 1, तो माँग अपेक्षाकृत लोचदार होती है (किसी उत्पाद की माँग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन क़ीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक है)। उदाहरण के लिए: शीघ्रता से बिकने वाली/गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ (Fast moving consumer goods), समाचार-पत्र, टमाटर की चटनी (Tomato ketchup) जैसी उपभोक्ता वस्तुएँ, चॉकलेट आदि।

C. आय लोच (Income Elasticity)

माँग की आय लोच से तात्पर्य उन उपभोक्ताओं की वास्तविक आय में परिवर्तन के प्रति किसी निश्चित वस्तु की माँग की मात्रा की संवेदनशीलता से है, जो इस वस्तु को ख़रीदते हैं (अन्य सभी कारकों के स्थिर/नियत रखते हुए)।

माँग की आय लोच का अर्थ है, माँग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा आय में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात।

$$\text{आय लोच} = \frac{\text{माँग की मात्रा में \% परिवर्तन}}{\text{आय में \% परिवर्तन}}$$

माँग की आय लोच के प्रकार (Types of Income Elasticity of Demand)

1. **माँग की धनात्मक आय लोच** (Positive Income Elasticity of Demand)**:** यदि उपभोक्ता की आय एवं वस्तु की माँग के बीच प्रत्यक्ष संबंध है, तो आय की लोच धनात्मक होगी। अर्थात, यदि किसी वस्तु की माँग की मात्रा उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है तथा उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ वस्तु की माँग की मात्रा में वृद्धि होती है, तो इसे माँग की धनात्मक आय लोच कहा जाता है। उदाहरण के लिए: जैसे-जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, वे बेहतर (विलासी) वस्तुओं का अधिक उपभोग करते हैं। इसके विपरीत, जैसे-जैसे उपभोक्ता की आय घटती है, वे विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपभोग कम करते हैं।
2. **माँग की ऋणात्मक आय लोच** (Negative Income Elasticity of Demand)**:** यदि उपभोक्ता की आय तथा वस्तु की माँग के बीच 'व्युत्क्रम संबंध' (Inverse relation) है, तो आय की लोच ऋणात्मक होगी। अर्थात, यदि किसी वस्तु की माँग की मात्रा, उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ घटती है या उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ वस्तु की माँग की मात्रा घटती है, तो इसे माँग की ऋणात्मक आय लोच कहा जाता है। उदाहरण के लिए: जैसे-जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, वे निम्नकोटि की वस्तुओं का उपभोग या तो बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं।
3. **माँग की शून्य आय लोच** (Zero Income Elasticity of Demand)**:** यदि किसी वस्तु के लिए माँग की मात्रा उपभोक्ता की आय में किसी भी प्रकार की वृद्धि या कमी के साथ स्थिर रहती है, तो इसे माँग की शून्य आय लोच कहा जाता है। उदाहरण के लिए: बुनियादी आवश्यक वस्तुओं, जैसे- नमक, मिट्टी का तेल, बिजली आदि के मामले में माँग की आय लोच शून्य होती है।

सामान्य वस्तुएँ और निम्नकोटि की वस्तुएँ (Normal Goods and Inferior Goods)**:** माँग की आय लोच के मूल्यों के आधार पर, वस्तुओं को व्यापक तौर पर निम्नकोटि तथा सामान्य वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. **सामान्य वस्तुएँ** (Normal Goods)**:** सामान्य वस्तुओं की माँग की आय लोच धनात्मक होती है। जैसे-जैसे आय बढ़ती है, प्रत्येक मूल्य स्तर पर अधिक वस्तुओं की माँग की जाती है। उपभोक्ता जिस वस्तु की माँग करता है उसकी मात्रा उसकी प्रकृति के आधार पर आय में वृद्धि के साथ बढ़ या घट सकती है। अधिकांश वस्तुओं के लिए, उपभोक्ता द्वारा चुनी जाने वाली मात्रा उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है तथा उपभोक्ता की आय घटने पर घट जाती है। ऐसी वस्तुओं को सामान्य वस्तुएँ कहा जाता है। इस प्रकार, एक उपभोक्ता की सामान्य वस्तु की माँग उपभोक्ता की आय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है।

   सामान्य वस्तुएँ, जिनकी माँग की आय लोच शून्य एवं एक के बीच होती है, उन्हें सामान्य तौर पर आवश्यक वस्तुओं के रूप में जाना जाता है, ये ऐसे उत्पाद तथा सेवाएँ हैं, जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के स्तर में परिवर्तन के बाद भी ख़रीदते हैं। आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं के उदाहरणों में प्रमुख खाद्य पदार्थ, जल तथा बिजली शामिल हैं।
2. **निम्नकोटि की वस्तुएँ** (Inferior Goods)**:** निम्नकोटि की वस्तुओं की माँग की आय लोच ऋणात्मक होती है। जैसे-जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, निम्नकोटि वाली वस्तुओं की माँग कम हो जाती है, और जैसे-जैसे आय घटती है, निम्नकोटि वाली वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है। निम्नकोटि की वस्तुओं के उदाहरणों में मोटे अनाज (Coarse cereals) जैसे निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

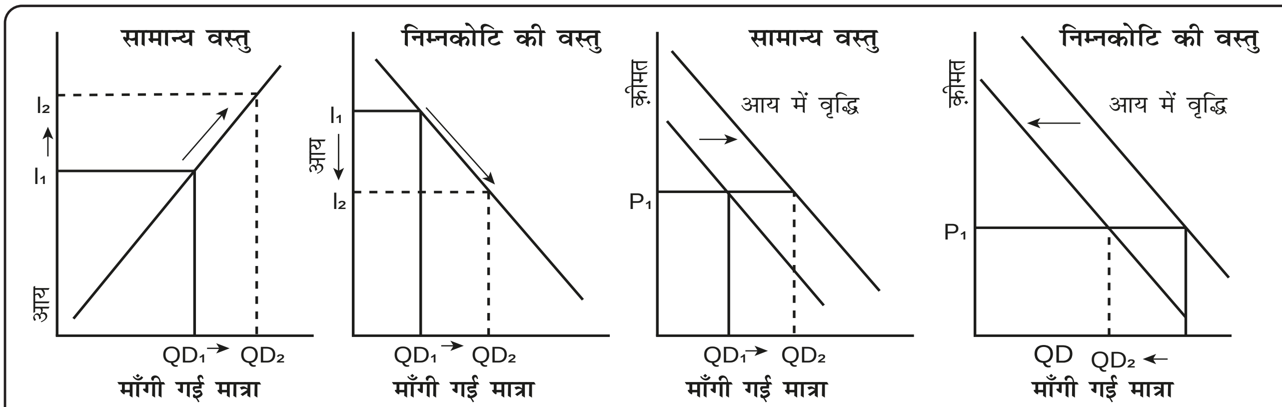

जैसे-जैसे आय बढ़ती है, माँग में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे माँग की मात्रा भी बढ़ती है

जैसे-जैसे आय घटती है माँग में वृद्धि होती है, माँग की मात्रा बढ़ती है

आय में वृद्धि (एक गैर-मूल्य कारक) के कारण दाईं ओर (धनात्मक) बदलाव होता है, इस प्रकार माँग में वृद्धि होती है

आय में वृद्धि के कारण बाईं ओर (ऋणात्मक) बदलाव होता है जिससे माँग घटती है

वस्तुओं के प्रकार और विशेषताएँ

स्थानापन्न वस्तुएँ	वस्तुएँ जो मूल वस्तुओं के उद्देश्य को पूरा करती हैं तथा विकल्प के रूप में उपयोग की जा सकती हैं। उदाहरण: मारुति कार को हुंडई कार से प्रतिस्थापित करना।
पूरक वस्तुएँ	एक वस्तु, जिसका उपयोग किसी संबद्ध, युग्मित या परस्पर संबंधित वस्तुओं के उपयोग से संबंधित है। यदि वस्तु A का अधिक उपयोग करने के लिए वस्तु B का अधिक उपयोग करने की आवश्यकता हो, तो दोनों वस्तुएँ (A और B) पूरक हैं।
गिफ़िन वस्तुएँ	एक वस्तु, जिसकी क़ीमत बढ़ने पर माँग बढ़ती है तथा क़ीमत घटने पर माँग गिर जाती है। उदाहरण: यदि मुख्य भोजन, जैसे- चावल, की क़ीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ताओं के पास अधिक महँगे खाद्य पदार्थ ख़रीदने के लिए कम पैसे होंगे, इसलिए वे अधिक चावल ख़रीदने के लिए विवश होंगे।
वेबलेन वस्तुएँ	विलासिता पूर्ण वस्तुओं के प्रकार, जिनकी क़ीमत बढ़ने पर माँग की मात्रा बढ़ जाती है। उदाहरण: लक्ज़री कारें, महँगी घड़ियाँ, महँगे इत्र
सामान्य वस्तुएँ	वह वस्तु, जिसकी माँग आय बढ़ने पर बढ़ती है तथा आय घटने पर माँग घटती है, बशर्ते कि क़ीमत स्थिर रहे। उदाहरण: ब्रेड (ब्रेड की गुणवत्ता आय पर निर्भर करती है)
निम्नकोटि की वस्तुएँ	वह वस्तु, जिसकी माँग आय बढ़ने पर घटती है तथा आय घटने पर बढ़ती है। उदाहरण: इसमें वे सभी वस्तुएँ एवं सेवाएँ शामिल हैं, जो केवल इसीलिए ख़रीदी जाती हैं, क्योंकि वे इन वस्तुओं के उच्च गुणवत्ता वाले विकल्प नहीं ख़रीद सकते हैं।

2.3 आपूर्ति (Supply)

2.3.1 आपूर्ति वक्र (Supply Curve)

आपूर्ति वक्र उत्पाद की क़ीमत एवं उस उत्पाद की मात्रा के बीच संबंध का आलेखी निरूपण है, जिसे विक्रेता आपूर्ति करने को इच्छुक और सक्षम है।

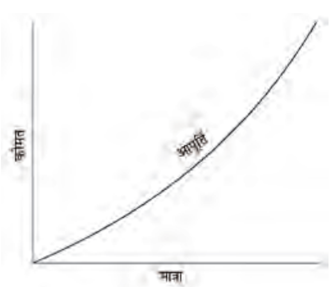

आपूर्ति वक्र

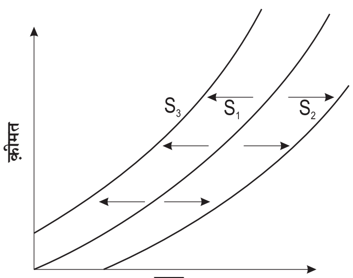

आपूर्ति में बदलाव

अधिकांश मामलों में, आपूर्ति वक्र को बाएँ से दाएँ ऊर्ध्वगामी बढ़ते ढाल (Rising upward slope) के रूप में रेखांकित किया जाता है, क्योंकि उत्पाद की क़ीमत तथा आपूर्ति की गई मात्रा प्रत्यक्षतः संबंधित होती है (अर्थात, जैसे-जैसे बाज़ार में किसी वस्तु की क़ीमत बढ़ती है, आपूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है)। यह संबंध अन्य कारकों के स्थिर रहने पर निर्भर है। ऐसे कारकों में बाज़ार में विक्रेताओं की संख्या, प्रौद्योगिकी की स्थिति, उत्पादन लागत का स्तर, विक्रेता की मूल्य अपेक्षाएँ (Seller's price expectations) और संबंधित उत्पादों की क़ीमतें शामिल हैं।

इनमें से किसी भी स्थिति में बदलाव से आपूर्ति वक्र में बदलाव आएगा। वक्र का बाईं ओर खिसकना आपूर्ति किए गए उत्पाद की मात्रा में कमी को दर्शाता है, जबकि दाईं ओर खिसकना वृद्धि को दर्शाता है।

2.3.2 आपूर्ति का नियम (Law of Supply)

आपूर्ति का नियम कहता है कि यदि अन्य कारक स्थिर रहते हैं, तो किसी वस्तु की क़ीमत और आपूर्ति की मात्रा प्रत्यक्षतः एक-दूसरे से संबंधित होती है। अन्य शब्दों में, जब किसी वस्तु के लिए ख़रीदारों द्वारा भुगतान की जाने वाली क़ीमत बढ़ जाती है, तो आपूर्तिकर्ता बाज़ार में उस वस्तु की आपूर्ति बढ़ा देते हैं।

जब किसी वस्तु की क़ीमत बढ़ती है, तो आपूर्तिकर्ता अधिक क़ीमतों के कारण लाभ अर्जित करने के लिए आपूर्ति बढ़ा देता है।

2.3.3 आपूर्ति के नियम की मान्यताएँ (Assumptions to the Law of Supply)

1. **उत्पादन की लागत स्थिर रहती है** (Cost of Production Remain Constant): यदि उत्पाद की क़ीमत में वृद्धि के साथ उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, तो विक्रेता या निर्माता को अधिक वस्तु का उत्पादन तथा आपूर्ति करना उचित नहीं लगेगा। उत्पादन लागत में मज़दूरी, ब्याज, किराया आदि का भुगतान करने में लगने वाली लागत शामिल होती है।
2. **प्रौद्योगिकी स्थिर रहती है** (Technology Remain Constant): वस्तु के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली तकनीक या प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उत्पादन की लागत समान बने रहने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है। यदि उन्नत तकनीक या 'तात्कालिक रूप से समायोजित तकनीक' (Improvised technique) से उत्पादन की लागत कम हो जाती है, तो निर्माता या विक्रेता गिरती क़ीमतों पर भी अधिक वस्तु का उत्पादन तथा आपूर्ति करेगा।
3. **परिवहन लागत स्थिर रहती है** (Transport Cost Remain Constant): परिवहन लागत में किसी भी बदलाव से उत्पादन की कुल लागत में बदलाव आएगा, परिवहन लागत में कमी निर्माता या आपूर्तिकर्ता को गिरती क़ीमत पर भी वस्तु का उत्पादन तथा आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
4. **संबंधित वस्तुएँ (स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तुएँ)** [Related Goods (Substitute Goods and Complementary Goods)]: संबंधित वस्तु की क़ीमत में कोई भी बदलाव वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित करेगा। यदि उत्पादक एक से अधिक वस्तुओं के उत्पादन में शामिल है, तो वह उस वस्तु का उत्पादन करने का इच्छुक होगा, जिसकी क़ीमत अधिक हो। इस परिस्थिति में, वस्तु की क़ीमत बढ़ने पर भी अधिक

उत्पाद का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना अधिक लाभदायक है।

2.3.4 आपूर्ति की लोच (Supply Elasticity)

किसी वस्तु की आपूर्ति की क़ीमत लोच उस वस्तु की क़ीमत में परिवर्तन के प्रति आपूर्ति की गई मात्रा की अनुक्रिया को मापती है। आपूर्ति की क़ीमत लोच को सविस्तार निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है:

$$\text{आपूर्ति की क़ीमत लोच } (E_S) = \frac{\text{आपूर्ति की मात्रा में \% परिवर्तन}}{\text{क़ीमत में \% बदलाव}}$$

आपूर्ति लोच के मामले (Cases of Elasticity Supply)

1. **लोचदार आपूर्ति** ($E_s > 1$): आपूर्ति को लोचदार तब कहा जाता है, जब क़ीमत में दिए गए प्रतिशत परिवर्तन से आपूर्ति की मात्रा में बड़ा बदलाव होता है। इस स्थिति में, E_s का संख्यात्मक मान एक से अधिक, लेकिन अनंत से कम होगा।
2. **बेलोचदार आपूर्ति** ($E_s < 1$): आपूर्ति को बेलोचदार तब कहा जाता है, जब क़ीमत में दिए गए प्रतिशत परिवर्तन के कारण आपूर्ति की मात्रा में कम बदलाव होता है। यहाँ आपूर्ति की लोच का संख्यात्मक मान शून्य से अधिक, लेकिन एक से कम है।
3. **आपूर्ति की इकाई लोच** ($E_s = 1$): यदि क़ीमत तथा आपूर्ति की मात्रा में समान परिमाण से परिवर्तन होता है, तो हमारे पास आपूर्ति की इकाई लोच होती है। आपूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुज़रने वाली एक सीधी रेखा है।

2.4 बाज़ार संतुलन (Market Equilibrium)

संतुलन में, कुल मात्रा, जिसे सभी 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान' (Firms) बेचना चाहते हैं, वह उस मात्रा के बराबर होती है, जिसे बाज़ार में सभी उपभोक्ता ख़रीदना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, बाज़ार आपूर्ति बाज़ार माँग के बराबर होती है। जिस क़ीमत पर संतुलन प्राप्त होता है, उसे **संतुलन क़ीमत** (Equilibrium price) कहा जाता है और इस क़ीमत पर ख़रीदी तथा बेची गई मात्रा को **संतुलन मात्रा** कहा जाता है।

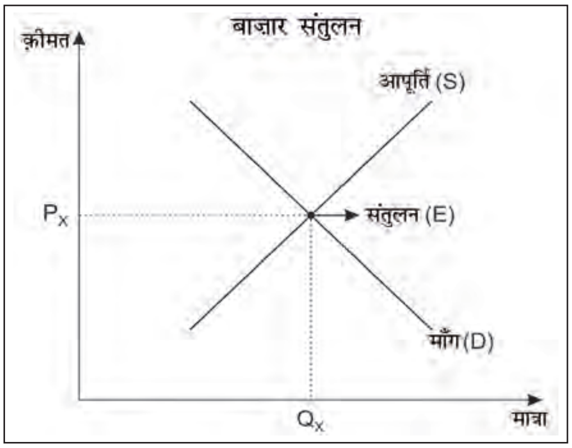

यदि किसी क़ीमत पर बाज़ार की आपूर्ति बाज़ार की माँग से अधिक है, तो हम कहते हैं कि उस क़ीमत पर बाज़ार में अतिरिक्त आपूर्ति/अधिपूर्ति (Excess supply) है तथा यदि किसी क़ीमत पर बाज़ार की माँग बाज़ार की आपूर्ति से अधिक है, तो यह कहा जाता है कि उस क़ीमत पर बाज़ार में अतिरिक्त माँग/अधिमाँग (Excess demand) मौजूद है। इसलिए, एक 'पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाज़ार' (Perfectly competitive market) में संतुलन को वैकल्पिक रूप से 'शून्य अधिमाँग-शून्य अधिपूर्ति स्थिति' (Zero excess demand-zero excess supply situation) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

2.5 बाज़ार संरचना (Market Structure)

2.5.1 पूर्ण प्रतिस्पर्धा (Perfect Competition)

पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक बाज़ार संरचना है, जिसमें ख़रीदारों और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, सभी बिना किसी प्रतिबंध या बाधाओं के सज़ातीय उत्पाद ख़रीदने तथा बेचने में सम्मिलित होते हैं तथा उस समय बाज़ार का सही ज्ञान रखते हैं। बाज़ार में प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता 'क़ीमत स्वीकार करने वाला' (Price taker) होता है।

पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तु की क़ीमत माँग एवं आपूर्ति की बाज़ार शक्तियों के माध्यम से तय होती है।

एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं:

1. **क्रेताओं एवं विक्रेताओं की बड़ी संख्या** (Large Number of Buyers and Sellers): एक पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी एक व्यक्ति क़ीमत एवं अंततः समग्र बाज़ार के उत्पादन को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है।
2. **समाँगी उत्पाद** (Homogeneous Products): एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार में प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान एक समाँगी उत्पाद प्रस्तुत करता है। इस प्रकार, किसी भी ख़रीदार को किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठान या विक्रेता के उत्पाद के लिए कोई प्राथमिकता नहीं होती है। इससे बाज़ार में क़ीमत में एकरूपता आती है।
3. **निःशुल्क प्रवेश एवं निकास** (Free Entry and Exit): कंपनियाँ उद्योग में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी कंपनी को भारी घाटा होता है, तो वह उद्योग छोड़ने तथा बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र है। उद्योग में नए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
4. **क़ीमत एवं प्रौद्योगिकी का पूर्ण ज्ञान** (Full Knowledge of Price and Technology): ख़रीदारों और विक्रेताओं को उत्पाद की क़ीमत तथा उत्पादन में उपयोग की जाने वाली तकनीक के बारे में पूरी जानकारी होती है। इससे बाज़ार में क़ीमत में एकरूपता आती है।

5. **परिवहन लागत का अभाव** (Absence of Transport Cost): यह एक आवश्यक शर्त है, क्योंकि समाँगी उत्पाद पूरे बाज़ार में एक ही क़ीमत पर बेचे जाते हैं। यदि परिवहन लागत को वस्तु के उत्पादन की लागत में जोड़ा जाता है, तो बाज़ार में उत्पाद की क़ीमत भिन्न हो सकती है, जिससे 'मध्यस्थता के अवसर' (Arbitrage opportunities) उत्पन्न हो सकते हैं और क़ीमत विकृत हो सकती है।

   पूर्ण प्रतिस्पर्धा को कभी-कभी "शुद्ध प्रतिस्पर्धा" (Pure competition) भी कहा जाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक काल्पनिक बाज़ार संरचना (Hypothetical market structure) है। इसका उपयोग मुख्य रूप से एक मानक के रूप में किया जाता है, जिसके विरुद्ध अन्य, वास्तविक बाज़ार संरचनाओं की तुलना की जाती है।

2.5.2 एकाधिकार (Monopoly)

एक बाज़ार संरचना, जिसकी विशेषता एक एकल विक्रेता है, जो बाज़ार में एक अद्वितीय उत्पाद बेचता है। एकाधिकारवादी बाज़ार में, विक्रेता को किसी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वह वस्तु का एकमात्र विक्रेता होता है, जिसका कोई निकटस्थ विकल्प नहीं होता है।

एकाधिकार एक लाभ अधिकतमकर्ता (Maximizer) है, क्योंकि वह लाभ अर्जित करने के लिए किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति तथा क़ीमत को बदल सकता है। यह उस बिंदु को निर्धारित करके उत्पादन का स्तर पा सकता है, जो इसके लाभ को अधिकतम करता है, जिस पर इसका सीमांत राजस्व (Marginal revenue) इसकी सीमांत लागत के बराबर होता है। एक एकाधिकारी व्यावसायिक प्रतिष्ठान मूल्य निर्धारक (Price maker) होता है।

एकाधिकार एक बाज़ार स्थिति है, जिसमें कोई एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रत्येक दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उत्पाद में मूल्य परिवर्तन से स्वतंत्र होता है।

एकाधिकार बाज़ार संरचना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. **एकल विक्रेता** (Single Seller): यह एकाधिकार की मुख्य विशेषता है। एकाधिकार बाज़ार की स्थितियों के तहत, उत्पादों का एक ही विक्रेता या निर्माता होता है। बाज़ार में उत्पादों की आपूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसके अलावा, एकाधिकार के तहत, विक्रेता को उत्पादों की क़ीमत तय करने की शक्ति प्राप्त होती है।

2. **उत्पाद का कोई स्थानापन्न नहीं** (No Substitutes of the Product): एकाधिकार के तहत, विक्रेता ऐसे उत्पाद का लेन-देन करता है, जो प्रकृति में अद्वितीय होता है तथा उसका कोई निकटस्थ स्थानापन्न नहीं होता है। एकाधिकार बाज़ार में उत्पादों का विभेदीकरण (Differentiation) नहीं होता है।

3. **प्रवेश में बाधाएँ** (Barriers to Entry): एकाधिकार के तहत, कई प्रवेश बाधाएँ हैं, जो नए संगठनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करती हैं। इन बाधाओं में अनन्य संसाधन स्वामित्व (Exclusive resource ownership), कॉपीराइट, उच्च प्रारंभिक निवेश तथा सरकार द्वारा अन्य प्रतिबंध शामिल हैं।

4. **सूचना पर प्रतिबंध** (Restriction on Information): एकाधिकार के तहत, सूचना संगठन तथा संगठन के भीतर काम करने वाले लोगों तक ही सीमित होती है। यह सूचना दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं होती है तथा इसे केवल कॉपीराइट एवं पेटेंट के रूप में अंतरित किया जा सकता है।

2.5.3 एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा (Monopolistic Competition)

एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा शब्द एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा का संयोजन है। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य ऐसी बाज़ार स्थिति से है, जिसमें उत्पादों के क्रेता एवं विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं। हालाँकि, प्रत्येक विक्रेता का उत्पाद किसी-न-किसी पहलू में भिन्न होता है।

यह एक ऐसे उद्योग की विशेषता है, जिसमें कई कंपनियाँ ऐसे उत्पाद या सेवाएँ प्रस्तुत करती हैं, जो समान हैं, लेकिन सर्वोत्तम विकल्प नहीं हैं। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बाज़ार शक्ति समान, अपेक्षाकृत कम स्तर की होती है; वे सभी क़ीमत निर्धारक होते हैं।

दीर्घावधि में, माँग अत्यधिक लोचदार होती है, जिसका अर्थ है कि यह मूल्य परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

1. **विक्रेताओं और क्रेताओं की बड़ी संख्या** (Large number of Vendors and Sellers): यह एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से एक को संदर्भित करता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के समान, एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा में भी विक्रेताओं और ख़रीदारों का आकार बड़ा होता है।

2. **विभेदीकृत उत्पाद** (Differentiated Products): यह एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा की विशेषता है। एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा के तहत, विक्रेताओं के उत्पाद कई मामलों में भिन्न होते हैं, जैसे ब्रांड, आकार, रंग, शैली, ट्रेडमार्क, टिकाऊपन तथा गुणवत्ता में अंतर। इसलिए, क्रेता एक से अधिक तरीकों से उपलब्ध उत्पादों के बीच आसानी से अंतर कर सकते हैं। हालाँकि, एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा के तहत, उत्पाद एक-दूसरे के निकटस्थ स्थानापन्न होते हैं।

3. **निःशुल्क प्रवेश एवं निकास** (Free Entry and Exit): एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा के तहत संगठनों पर बाज़ार में प्रवेश तथा निकास के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। यह वही स्थिति है, जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में प्रचलित होती है।

4. **मूल्य नीति** (Price Policy): यह किसी उत्पाद की बाज़ार क़ीमतों को प्रभावित करती है। एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा में, यदि उत्पादों की क़ीमतें अधिक हैं, तो ख़रीदार उत्पादों की निकट प्रतिस्थापन क्षमता के कारण अन्य विक्रेताओं के पास चले जाएँगे। इसलिए, एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा में संगठनों को क़ीमत पर पूर्ण नियंत्रण का लाभ नहीं मिलता है।

   वास्तविक दुनिया में अधिकांश छोटी कंपनियाँ ऐसे बाज़ारों में काम करती हैं, जिन्हें एकाधिकार की दृष्टि से प्रतिस्पर्धी कहा जा सकता है।

   प्रतिस्पर्धा के एक आर्थिक मॉडल के रूप में, एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना में अधिक यथार्थवादी है - कई परिचित और सामान्य बाज़ारों (Commonplace markets) में इस मॉडल की कई विशेषताएँ हैं।

2.5.4 अल्पाधिकारवादी (Oligopoly)

अल्पाधिकारवाद एक बाज़ार संरचना है, जिसमें कम कंपनियों के पास बाज़ार हिस्सेदारी का बड़ा हिस्सा होता है। अल्पाधिकारवाद एकाधिकारवाद के समान है, सिवाय इसके कि एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के बजाय, दो या दो से अधिक कंपनियाँ बाज़ार पर प्रभावी होती हैं। एक अल्पाधिकारवाद में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या की कोई सटीक ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन संख्या इतनी कम होनी चाहिए कि एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के कार्य दूसरों को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करें। अल्पाधिकारवाद की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

1. **कुछ विक्रेता तथा कई क्रेता** (Few Sellers and Many Buyers): अल्पाधिकारवाद के तहत, कुछ विक्रेता पूरे उद्योग पर प्रभावी होते हैं। ये विक्रेता एक-दूसरे की क़ीमतों को प्रभावित करते हैं।
2. **समरूप या विभेदीकृत उत्पाद** (Homogeneous or Differentiated Products): अल्पाधिकारवाद में, संगठन या तो समरूप उत्पाद (पूर्ण प्रतिस्पर्धा के समान) या विभेदीकृत उत्पाद (एकाधिकार के मामले में) का उत्पादन करते हैं।
3. **प्रवेश एवं निकास में बाधाएँ** (Barriers in Entry and Exit): प्रवेश एवं निकास की बाधाएँ अल्पाधिकारवाद बाज़ार को एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा से अलग करती हैं।
4. **पारस्परिक अन्योन्याश्रयता** (Mutual Interdependence): पारस्परिक अन्योन्याश्रयता का अर्थ है कि संगठन एक-दूसरे के निर्णयों से प्रभावित होते हैं। इन निर्णयों में संगठनों के मूल्य निर्धारण तथा उत्पादन संबंधी निर्णय शामिल हैं।
5. **एकरूपता का अभाव** (Lack of Uniformity): अल्पाधिकार में, संगठन अपने आकार में एकसमान नहीं होते हैं। कुछ संगठन आकार में बहुत बड़े होते हैं, जबकि कुछ बहुत छोटे होते हैं।
6. **मूल्य कठोरता की स्थिति** (Existence of Price Rigidity): इसका तात्पर्य यह है कि संगठन अल्पाधिकारवाद में अपने उत्पादों की क़ीमतों में बदलाव करना पसंद नहीं करते हैं। यदि कोई संगठन अपने उत्पादों की क़ीमत कम करता है, तो उसके प्रतिद्वंद्वी भी क़ीमतें कम कर देते हैं, जिससे संगठन के लाभ अर्जन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, कंपनियाँ मूल्य संघर्ष से बचने के लिए निहित क़ीमतों पर कायम रहती हैं।

   एकाधिकारवाद तथा पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, संगठन अन्य संगठनों के निर्णयों तथा प्रतिक्रियाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं, इसलिए, इस प्रकार की बाज़ार संरचनाओं में संगठनों के निर्णय स्वतंत्र होते हैं। हालाँकि, अल्पाधिकारवाद में, एक संगठन स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है और उसे अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।

   भारत में, दूरसंचार सेवाओं, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, आदि के बाज़ार अल्पाधिकारवाद बाज़ार के उदाहरण हैं। इन सभी बाज़ारों में, प्रत्येक विशेष उत्पाद के लिए कुछ कंपनियाँ हैं।

आयाम (Dimensions)	पूर्ण प्रतिस्पर्धा (Perfect Competition)	एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा (Monopolistic Competition)	अल्पाधिकारवाद (Oligopoly)	एकाधिकारवाद (Monopoly)
विक्रेताओं की संख्या	कई	कई	कुछ	एक
प्रवेश में बाधाएँ	बहुत कम	कम	उच्च	बहुत उच्च
स्थानापन्न के प्रकार	बहुत अच्छा	अच्छा स्थानापन्न किंतु विभेदीकृत	बहुत अच्छा विभेदीकृत स्थानापन्न	अच्छा स्थानापन्न नहीं
प्रतिस्पर्धा का स्वरूप	केवल क़ीमत	विपणन, विशेषताएँ और क़ीमत	विपणन, विशेषताएँ और क़ीमत	विज्ञापन
मूल्य निर्धारण की शक्ति	कोई भी नहीं	थोड़ा	कम से लेकर महत्त्वपूर्ण तक	महत्त्वपूर्ण

2.5.5 एकक्रेताधिकार (Monopsony)

एकक्रेताधिकार में, जिसे कभी-कभी क्रेता के एकाधिकार (Buyer's monopoly) के रूप में जाना जाता है, एकाधिकारवाद के समान बाज़ार की स्थिति होती है, सिवाय इसके कि एक बड़ा क्रेता/ख़रीदार, न कि विक्रेता, बाज़ार के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है तथा क़ीमतों को नीचे लाता है। एकक्रेताधिकार की स्थिति

वह होती है, जब एक एकल व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पास अपने उत्पादन के कारकों को नियोजित करने की बाज़ार शक्ति होती है।

उदाहरण के लिए, प्रौद्योगिकी उद्योग एक एकक्रेताधिकार है। इंजीनियरों के लिए बाज़ार में केवल कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों के साथ, सिस्को एवं ओरेकल जैसे प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर तकनीकी पदों पर वेतन को लेकर एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा न करने तथा मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया है, जिससे वेतन कम दिया जाता है ताकि प्रमुख तकनीकी कंपनियों को कम परिचालन लागत एवं अधिक लाभ की प्राप्ति हो। यह उदाहरण इस तथ्य पर भी प्रकाश डालता है कि कंपनियों का एक समूह एक एकक्रेताधिकार के रूप में कार्य कर सकता है।

2.6 लाभ निर्धारण का अर्थशास्त्र (Economics of Profit Determination)

उत्पादन की लागत (Cost of Production)

उत्पादन लागत से तात्पर्य किसी व्यवसाय द्वारा किसी वस्तु के निर्माण या सेवा प्रदान करते समय लगने वाली लागत से है। उत्पादन लागत में श्रम, कच्चे माल, उपभोज्य विनिर्माण आपूर्ति (Consumable manufacturing supplies) एवं सामान्य उपरिव्यय (General overhead) सहित कई प्रकार के ख़र्च शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी कर या प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण वाली कंपनियों द्वारा बकाया रॉयल्टी को भी उत्पादन लागत माना जाता है।

स्थिर एवं परिवर्तनीय लागत (Fixed and Variable Cost)

स्थिर लागत वे हैं, जो उत्पादन के साथ भिन्न नहीं होती हैं तथा सामान्य तौर पर इसमें किराया, बीमा, मूल्यह्रास (Depreciation), स्थापन लागत (Set-up costs) शामिल होती हैं।

परिवर्तनीय लागत वह लागत है, जो उत्पादन के साथ बदलती रहती है, तथा उसे प्रत्यक्ष लागत भी कहा जाता है। विशिष्ट परिवर्तनीय लागतों के उदाहरणों में ईंधन, कच्चा माल और कुछ श्रम लागतें शामिल हैं।

कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्तनीय लागत (Total Fixed Cost and Total Variable Cost)

यह देखते हुए कि उत्पादन बढ़ने पर कुल स्थिर लागत (TFC) स्थिर रहती है, वक्र लागत ग्राफ़ पर एक क्षैतिज रेखा है, क्योंकि कुल निश्चित लागत उत्पादन की मात्रा के बावजूद स्थिर रहती है तथा उत्पादन के शून्य स्तर पर शून्य नहीं होती है। कुल परिवर्तनीय लागत (TVC) वक्र त्वरित दर से उर्ध्वगामी ढाल वाला होता है, जो घटते सीमांत प्रतिफल (Marginal returns) के नियम को दर्शाता है।

कुल लागत (Total Cost)

कुल लागत (TC) वक्र कुल स्थिर एवं कुल परिवर्तनीय लागत को जोड़कर बनता है।

औसत स्थिर लागत (Average Fixed Cost)

कुल स्थिर लागत को उत्पादन से विभाजित करके औसत स्थिर लागत निकाला जाता है। चूँकि स्थिर लागत को बढ़ते उत्पादन से विभाजित किया जाता है, औसत स्थिर लागत कम होती जाएगी। औसत स्थिर लागत (AFC) वक्र लगातार बाएँ से दाएँ नीचे की ओर ढलता जाएगा।

$$\text{औसत स्थिर लागत} = \frac{\text{कुल स्थिर लागत}}{\text{उत्पादन}}$$

औसत परिवर्तनीय लागत (Average Variable Cost)

कुल परिवर्तनीय लागत को उत्पादन से विभाजित करके औसत परिवर्तनीय लागत प्राप्त होती है। औसत परिवर्तनीय लागत (AVC) वक्र पहले बाएँ से दाएँ नीचे की ओर झुकेगा, फिर न्यूनतम बिंदु तक पहुँचेगा और फिर से ऊपर उठेगा।

$$\text{औसत परिवर्तनीय लागत} = \frac{\text{कुल परिवर्तनीय लागत}}{\text{उत्पादन}}$$

औसत कुल लागत (Average total cost)

औसत कुल लागत (ATC) को औसत लागत या इकाई लागत भी कहा जाता है। औसत कुल लागत व्यावसायिक प्रतिष्ठान के सिद्धांत में एक महत्त्वपूर्ण लागत है, क्योंकि यह इंगित करती है कि दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कितनी दक्षता से किया जा रहा है।

औसत कुल लागत = औसत स्थिर लागत + औसत परिवर्तनीय लागत

औसत कुल लागत वक्र भी 'U' आकार का है, क्योंकि यह औसत परिवर्तनीय लागत वक्र से अपना आकार लेता है, जिसमें उछाल परिवर्तनीय कारक पर घटते प्रतिफल की शुरुआत को दर्शाता है।

सीमांत लागत (Marginal cost)

सीमांत लागत उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत है। इसे उत्पादन में एक इकाई बढ़ने पर कुल लागत में परिवर्तन की गणना करके प्राप्त किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि सीमांत लागत पूर्णतः परिवर्तनीय लागत से प्राप्त होती है, न कि स्थिर लागत से।

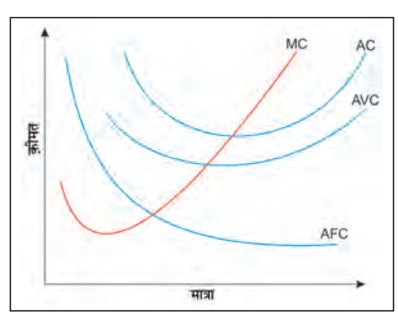

सीमांत लागत

सीमांत लागत वक्र आरंभ में थोड़े समय के लिए गिरता है, फिर ऊपर उठता है। सीमांत लागतें परिवर्तनीय लागतों से प्राप्त होती हैं तथा 'परिवर्तनीय अनुपात के सिद्धांत' (Principle of

variable proportions) के अधीन होती हैं। यह अग्रणी लागत वक्र (Leading cost curve) है, क्योंकि कुल एवं औसत लागत में परिवर्तन सीमांत लागत में परिवर्तन से प्राप्त होते हैं।

औसत कुल लागत एवं सीमांत लागत (Average Total Cost and Marginal Cost)

एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान सबसे कम औसत कुल लागत पर सर्वाधिक उत्पादक रूप से दक्ष होता है, जो कि औसत कुल लागत (ATC) = सीमांत लागत (MC) भी है। ऐसा तब होता है, जब व्यावसायिक प्रतिष्ठान ने अपनी स्थिर लागत को कवर कर लिया हो तथा उत्पादन की लागत औसतन एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के बराबर हो।

अवसर लागत (Opportunity Cost)

अवसर लागत उस लाभ को संदर्भित करती है, जो एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने कार्रवाई का दूसरा तरीका अपनाने के कारण त्याग दिया। अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प की लागत का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए, यह लागत दो परस्पर अनन्य घटनाओं के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है।

विभिन्न निवेशों की संभावित लाभप्रदता का आकलन करते समय, व्यवसाय उस विकल्प की तलाश करते हैं, जिससे सर्वाधिक प्रतिफल मिलने की संभावना हो। प्रायः, यह किसी दिए गए निवेश साधन के लिए प्रतिफल की अपेक्षित दर को देखकर निर्धारित किया जा सकता है। हालाँकि, व्यवसायों को प्रत्येक विकल्प की अवसर लागत पर भी विचार करना चाहिए। मान लें कि, निवेश के लिए एक निश्चित राशि को देखते हुए, किसी व्यवसाय को प्रतिभूतियों में धन निवेश करने या नए उपकरण (Equipment) ख़रीदने के लिए इसका उपयोग करने के बीच चयन करना होगा। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन-सा विकल्प चुना गया है, दूसरे विकल्प में निवेश न करने से जो संभावित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, उसे अवसर लागत कहा जाता है। इसे प्रायः प्रत्येक विकल्प के अपेक्षित प्रतिफल के बीच अंतर के रूप में व्यक्त किया जाता है:

अवसर लागत = सबसे आकर्षक विकल्प (Most Lucrative option) पर प्रतिफल – चुने गए विकल्प (Chosen option) पर प्रतिफल

कुल राजस्व (Total Revenue)

कुल राजस्व वह कुल प्राप्तियाँ हैं, जो एक विक्रेता ख़रीदारों को सामान या सेवाएँ बेचकर प्राप्त कर सकता है। इसे $P \times Q$ के रूप में लिखा जा सकता है, जो बेची गई वस्तुओं की मात्रा से वस्तु की क़ीमत को गुणा करके प्राप्त होता है। विक्रेता के लिए लाभ कुल राजस्व में से कुल लागत घटाकर प्राप्त होगा। यह लाभ तब अधिकतम होगा, जब एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से सीमांत राजस्व ऐसी इकाई के उत्पादन की सीमांत लागत से अधिक या उसके बराबर होगा। प्रत्येक बाज़ार में व्यावसायिक प्रतिष्ठान को एक अलग आकार के राजस्व वक्र (Revenue curve) का सामना करना पड़ता है।

■■■■

विगत् वर्षों की प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों का अभ्यास कीजिए

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाज़ार माँग बढ़ सकती है, यदि

1. इसकी स्थानापन्न वस्तु (Substitute) की क़ीमत में वृद्धि हो
2. इसकी पूरक वस्तु (Complement) की क़ीमत में वृद्धि हो
3. वस्तु घटिया (Inferior) किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है
4. इसकी क़ीमत घटती है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 4
(b) 2, 3 और 4
(c) 1, 3 और 4
(d) 1, 2 और 3

(2021)

उत्तर. (a)